https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'यह वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर विकासवाद की जीत है'

वर्ष-13, अंक-01 01-15 जनवरी, 2018 (पाक्षिक) ₹20

गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने लहराया परचम

कांग्रेस ने खोया एक और राज्य

सामाजिक रचना का आधार

विश्वसनीयता और लोकप्रियता के एसिड टेस्ट में फिर खरे उतरे नरेंद्र मोदी

नए भारत के लिए जनादेश

दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में जीत के जश्न की छवियां

भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते भाजपा संसदीय दल के सदस्यों के साथ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

भाजपा मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

भाजपा मुख्यालय में गुजरात और हिमाचल की जीत के जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

भाजपा मुख्यालय में भाजपा की विजय पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 गुजरात में फिर भाजपा सरकार हिमाचल में खिला कमल

भारतीय जनता पार्टी का विजय-रथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में संपन्न गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जीत का परचम...

वैचारिकी

सामाजिक रचना का आधार 16

श्रद्धांजलि

स्वामी विवेकानंद 18

लेख

विश्वसनीयता और लोकप्रियता के एसिड टेस्ट में फिर खरे उतरे नरेंद्र... 19

नए भारत के लिए जनादेश 20

अन्य

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 30 करोड़ से भी अधिक खाते 14

रोजगार पैदा करने हेतु कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना को मंजूरी 21

चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए विशेष पैकेज... 22

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालयः वर्षान्त समीक्षा-2017 24

प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान 'ओखी' से प्रभावित लोगों से मुलाकात... 26

उद्योग संघों को देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करना... 27

कौशल उन्नयन के लिए 2,327 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित 28

सरकारी संस्थानों पर होने वाले साइबर हमलों से रक्षा करेगा... 29

मिशन इन्द्रधनुष के तहत 2.5 करोड़ बच्चे लाभान्वितः जे.पी. नड्डा 30

भारत और मोरक्को ने जल संसाधन, सड़क और समुद्री क्षेत्रों में... 31

परिवहन से परिवर्तन लाना हमारा मकसदः नरेंद्र मोदी 32

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04

पत्र-पत्रिकाओं से 33

स्फुट विचार 33

संगठनात्मक गतिविधियां

10 विकास ही देश का मंत्र है, विकास की ही जीत होगी: नरेन्द्र मोदी

गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि...

12 भाजपा ने महाराष्ट्र में 10 स्थानीय निकायों में 6 पर जीत दर्ज की

उत्तर प्रदेश के गत विधानसभा चुनाव की तरह नगर निकाय चुनावों में भी भारतीय...

सरकार की उपलब्धियां

13 आईएनएस कलवरी राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 दिसम्बर को नौसेना गोदी, मुम्बई में आयोजित एक शानदार समारोह में आईएनएस कलवरी (एस-21) का...

15 आइजोल की तुरिअल पन-बिजली परियोजना राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 दिसंबर को मिजोरम के आइज़ोल में 60 मेगावॉट की तुरिअल...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

जीता विकास, जीता गुजरात। जय जय गरवी गुजरात! हिमाचल प्रदेश में लहराया कमल, विकास की हुई भव्य जीत।

@AmitShah

गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत जातिवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकासवाद की जीत है।

@rajnathsingh

सशस्त्र बल ध्वज दिवस पर हम अपने सैनिकों और वरिष्ठों के साहस, बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान को नमन और आदर करते हैं। हमारी सशस्त्र सेना हमेशा हमारे देश का गौरव अक्षुण्ण रखेगी। मैं नागरिकों से http://ksb.gov.in/FundPayment.htm पर जाकर स्वेच्छा से योगदान करने का आग्रह करता हूं।

facebook

'मुख्यमंत्री सौर-शक्ति योजना' ऐसी पहल है, जिसके ज़रिए छत्तीसगढ़ के नागरिक स्वयं अपने घर की छत में सोलर ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन कर प्रदेश को विद्युत के क्षेत्र में नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं।

— डॉ. रमन सिंह

देवघर में एम्स अस्पताल के लिए जमीन का आवंटन कर दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि हर झारखण्डवासी को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। निरोग झारखण्ड बनाने की ओर ये एक और कदम है।

— रघुबर दास

सरकारी खजाने से 89.4 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद भ्रष्टाचार के चलते सातवीं बार जेल गए, लेकिन अपनी तुलना वे नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जैसे नेताओं से कर रहे हैं। आत्मश्लाघा और अवैध संपत्ति बनाने में लोकलाज खो देनेवाले लोग कैसा नेतृत्व करेंगे?

— सुशील कुमार मोदी

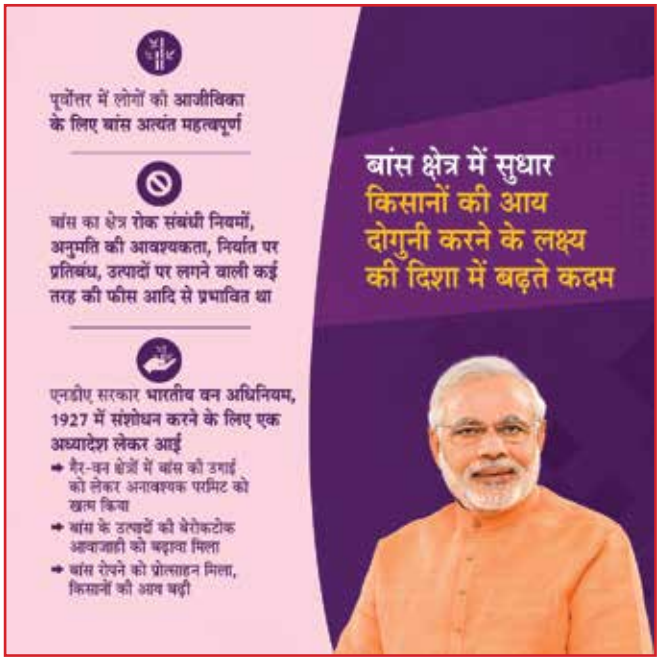

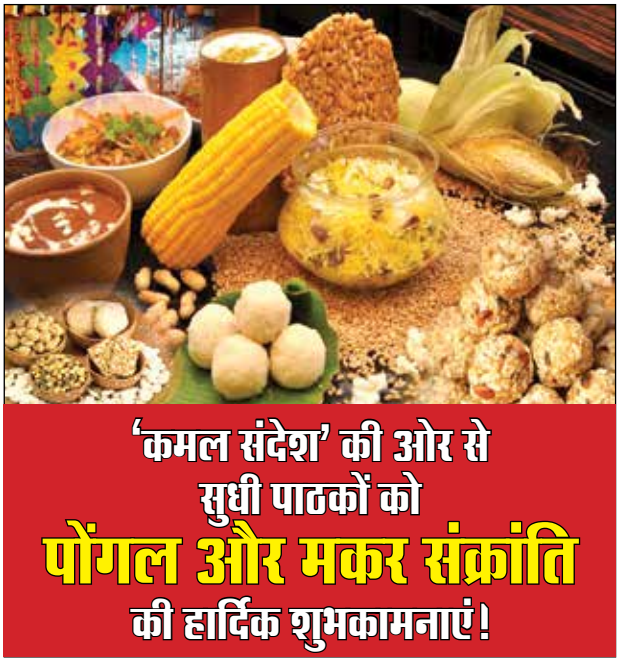

पराजित हुई कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति

गुजरात एवं हिमाचल की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। यह ऐसा जनादेश है जो जनता को गुमराह करने के अथक प्रयासों के बीच आया है। कांग्रेस का जातिवादी राजनीति के प्यादों के बल पर चुनाव जीतने का सपना धरा रह गया। जनता के स्पष्ट जनादेश से उन लोगों को गहरा झटका लगा है जो वंशवाद, जातिवाद एवं सांप्रदायिकता को चुनावों में अब भी प्रासंगिक मानते हैं। कांग्रेस का सोचना कि विकास का मजाक उड़ाने से लोग उसके कुशासन एवं भ्रष्टाचार को भूल जायेंगे, उस पर भारी पड़ी। येन–केन–प्रकारेण सत्ता पर काबिज होने की जल्दी कांग्रेस को हमेशा सिद्धांतहीन एवं समझौतावादी राजनीति की ओर धकेलती रही है। अपने संगठन को चुस्त-दुरुस्त बनाने तथा रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की जगह कांग्रेस ने जातिवादी राजनीति का सहारा लेकर समाज को विभाजित करने का प्रयास किया, जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ी। यह विडंबना ही थी कि एक ओर जहां राहुल गांधी वोटों के लिये मंदिरों के चक्कर लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर के निर्माण में इसके नेता कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालय में रोड़े अटका रहे थे। आरक्षण, नोटबंदी एवं जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस का विकास–विरोधी एवं जन–विरोधी चेहरा सामने आ गया। कई मुद्दों पर इसका दोमुंहापन बेनकाब हो गया तथा हार को सामने देखकर इसके नेता देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध अनाप–शनाप बोलने लगे। गुजरात एवं हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को चुनावों में अच्छा सबक सिखाया है और अब कांग्रेस के हाथों से एक और प्रदेश निकल चुका है।

> नरेन्द्र मोदी की रचनात्मक एवं परिवर्तनकारी कदमों के परिणाम आने लगे हैं तथा भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ रही है। देश के गरीब एवं वंचितों का भरोसा व्यवस्था पर एक बार पुनः स्थापित हुआ है और नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उनका विश्वास और अधिक दृढ़ होता जा रहा है। कांग्रेस जब–तक भ्रष्टाचारियों एवं घोटालेबाजों का साथ देती रहेगी, देश के गरीब–वंचितों का विश्वास नहीं जीत सकती।

कांग्रेस को सबसे बड़ी नाकामी इसके द्वारा रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में इसकी असमर्थता है। यह अब तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई कि जनता ने इसे कुशासन, भ्रष्टाचार, पॉलिसी पैरालिसिस तथा जनता के धन की खुली लूट के लिये ठुकराया है। विडंबना यह है कि यह अब भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांस्फॉर्म' के एजेंडे को किसी प्रकार से नीचा दिखाने में लगी है। इसने जानबूझकर नोटबंदी का विरोध किया, ताकि भ्रष्टाचारियों को बचाया जा सके। इससे गरीब और वंचित कांग्रेस से और भी अधिक दूर चले गये और यह भ्रष्टाचार एवं लूट की प्रतीक बन गई। यह संसद तथा जीएसटी काउंसिल में जीएसटी के पक्ष में दिखी, पर बाहर जीएसटी का विरोध कर अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने में लग गई। उसे उम्मीद थी कि जीएसटी का विरोध कर वह राजनैतिक लाभ उठा सकती है, परन्तु हुआ इसके ठीक विपरीत। इसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और यह पूरी तरह बेनकाब हो गई। एक ओर जब पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी छाप छोड़ रहा है तथा विश्व को अनेक रेटिंग एजेंसियां इस पर अपनी मुहर लगा रही हैं। वहीं, कांग्रेस विरोध का राग अलाप कर अपनी फजीहत करा रही है। विकास के विरुद्ध वातावरण बनाने की इसकी कोशिश तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के उदय पर प्रश्नचिह्न खड़े करने के इसके प्रयास को जनता ने बार–बार नकार दिया है।

भारत विकास के लगभग हर वैश्विक मानक पर खरा उतर रहा है ओर इसकी आर्थिक दृढ़ता देश की निरंतर बढ़ती सम्भावनाओं की प्रतीक बन गई है। इस सबके बावजूद कांग्रेस का एक तरफा प्रोपगेंड़ा, इसकी नकारात्मक राजनीति और प्रतिगामी मानसिकता का ही परिचय देता है।

कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिये कि इसने एक और प्रदेश गंवा दिया है। नरेन्द्र मोदी की रचनात्मक एवं परिवर्तनकारी कदमों के परिणाम आने लगे हैं तथा भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ रही है। देश के गरीब एवं वंचितों का भरोसा व्यवस्था पर एक बार पुनः स्थापित हुआ है और नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उनका विश्वास और अधिक दृढ़ होता जा रहा है। कांग्रेस जब–तक भ्रष्टाचारियों एवं घोटालेबाजों का साथ देती रहेगी, देश के गरीब–वंचितों का विश्वास नहीं जीत सकती। अपनी इस दुरवस्था में भी वंशवाद की राजनीति से चिपके रहने की इसकी आदत से स्पष्ट है कि इसका देश की लोकतांत्रिक भावनाओं से कोई लेना–देना नहीं है। देश में वंशवाद एवं जातिवाद के जहर को बोने के इसके प्रयासों को देश की जनता द्वारा कड़ा प्रत्युत्तर मिलता रहेगा। गुजरात एवं हिमाचल की अपनी हार से कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

गुजरात में फिर भाजपा सरकार

लगातार छठी बार लहराया जीत का परचम

हिमाचल में खिला कमल

मिला दो-तिहाई बहुमत

भारतीय जनता पार्टी का विजय-रथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में संपन्न गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जीत का परचम लहरा दिया। गुजरात में पार्टी ने लगातार छठी बार सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की, जबकि हिमाचल प्रदेश में उसने दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करते हुए कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया।

गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से भाजपा ने 99 सीटों पर विजय पताका फहराई, जबकि कांग्रेस के खाते में कुल 77 सीटें गईं। वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की। राज्य की कुल 68 सीटों में से उसने 44 सीटें जीतीं, वहीं कांग्रेस को 21 सीटों से संतोष करना पड़ा।

भाजपा के लिए यह अच्छा संदेश है कि कांग्रेस विमुद्रीकरण और जीएसटी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही थी, ऐसे में मतदाताओं ने दोनों राज्यों में भाजपा के पक्ष में बहुमत देकर इन पर अपनी मुहर लगा दी।

गुजरात-हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में आए नतीजों के साथ अब देश के 19 राज्यों में भाजपा व उसके सहयोगी दलों की सरकारें हो जाएंगी। दोनों राज्यों में जीत के साथ ही देश की 67 प्रतिशत आबादी और 78 प्रतिशत भू-भाग पर भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों का शासन हो गया है, जबकि कांग्रेस एक केंद्र शासित प्रदेश समेत पांच राज्यों और 7.78 प्रतिशत आबादी तक सिमट गई है।

परिणाम विकास के एजेंडा में जनता का विश्वास दर्शाते हैं : विजय रूपाणी

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत विकास तथा जाति और वर्गविहीन समाज के एजेंडों में जनता के अडिग विश्वास को दर्शाती है। श्री रूपाणी ने ट्वीट किया, "मैं नम्रता से लोगों का फैसला स्वीकार करता हूं, जिन्होंने भाजपा के लिए वोट किया और सुशासन की राजनीति में अपना विश्वास फिर से दिखाया, जिसे भारतीय राजनीति के परिदृश्य पर स्थापित करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता हैं। उन्होंने कहा, "धन्यवाद गुजरात! यह गुजरात के लोगों की जीत है, विकास तथा जाति और वर्ग विहीन समाज के एजेंडों में उनका अडिग विश्वास है। हमें वास्तव में आशीर्वाद मिला है। हम उम्मीदों पर पहले से अधिक खरा उतरने का प्रयास करेंगे।"

भाजपा मुख्यालय में जश्न

गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर दिल्ली में जोरदार जश्न मनाया गया। शुरुआती रुझान सामने आने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से नेता व कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय अशोक रोड पहुंचने लगे। यहां ढोल नगाड़ों, रंग व आतिशबाजी के बीच दिन भर जश्न का माहौल रहा। जश्न के दौरान दिल्ली के नेता व बड़ी संख्या में युवा और महिला कार्यकर्ता जमकर ढोल व नगाड़ों पर थिरके।

भाजपा कार्यालय पर पहुंचे कार्यकर्ताओं के जश्न में होली और दीपावली जैसा हर्ष एक साथ नजर आया। कार्यकर्ताओं ने रंग खेलकर जीत पर अपनी खुशी जाहिर की और जमकर आतिशबाजी की। कई कार्यकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ पहुंचे थे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह सायंकाल पार्टी मुख्यालय पहुंचे। यहां गुलाब की पंखुड़ियों से उनका स्वागत किया गया।

पारंपरिक वेशभूषा पहनकर आए पंजाबी कलाकारों ने भंगड़े पर लोगों के साथ जमकर नृत्य किया। वहीं, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी डांडिया लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचीं थीं। इन महिलाओं ने डांडिया खेल कर अपनी खुशी जाहिर की।

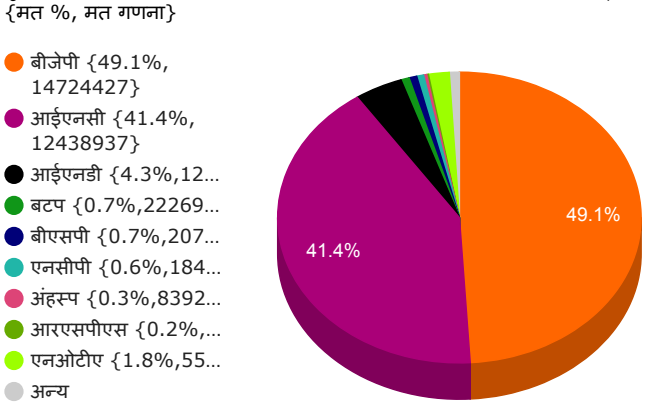

गुजरात परिणाम स्थिति		
182 निर्वाचन क्षेत्रों में से 182 की ज्ञात स्थिति		
दल का नाम	**विजयी**	**कुल**
इंडियन नेशनल कांग्रेस	77	77
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	1	1
भारतीय जनता पार्टी	99	99
भारतीय ट्रायबल पार्टी	2	2
निर्दलीय	3	3
कुल	**182**	**182**

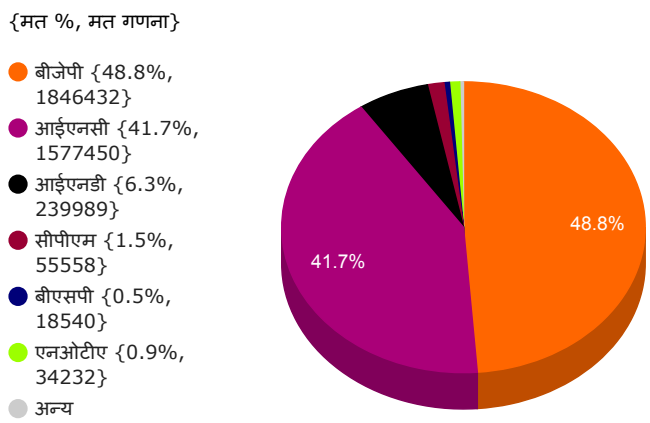

हिमाचल प्रदेश
परिणाम स्थिति

68 निर्वाचन क्षेत्रों में से 68 की ज्ञात स्थिति

दल का नाम	विजयी	कुल
इंडियन नेशनल कांग्रेस	21	21
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	1	1
भारतीय जनता पार्टी	44	44
निर्दलीय	2	2
कुल	**68**	**68**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह

समाचार–पत्रों की सुर्खियां

गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत को राष्ट्रीय समाचार–पत्रों ने महत्वपूर्ण बताते हुए इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व का परिणाम बताया। प्रस्तुत है समाचार–पत्रों की सुर्खियां —

गुजरात का हाथ, विकास के साथ– *नई दुनिया*

दोनों राज्यों में भाजपा का परचम– *जनसत्ता*

मोदी पर भरोसा– *राष्ट्रीय सहारा*

मोदी सबसे बड़े खेवैया– *दैनिक जागरण*

मोदी की जय– *नवभारत टाइम्स*

'ब्रांड मोदी' ने हिमाचल जिताया, गुजरात बचाया– *हिंदुस्तान*

न महेंद्र, न अमरेंद्र सिर्फ नरेंद्र बाहुबली– *नवोदय टाइम्स*

हैप्पी न्यू ईयर मोदी– *दैनिक ट्रिब्यून*

गुजरात में भाजपा की बादशाहत बरकरार, हरा हिमाचल भी हुआ भगवा– *पायनियर*

गढ़ बचाया, हिमाचल छीना– *अमर उजाला*

मोदी मैजिक– *पंजाब केसरी*

इनका कहना है-

गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम मोदी सरकार की नीतियों का अनुमोदन हैं।

— **राजनाथ सिंह**, केन्द्रीय गृहमंत्री

यह देश की जनता को तय करना होता है कि किसके नेतृत्व में किस दल की सरकार सभी के कल्याण के लिए काम कर सकती है। इस परिणाम ने यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुआई में 'सबका साथ सबका विकास' हो रहा है।

— **निर्मला सीतारमन**, केंद्रीय रक्षा मंत्री

मौजूदा राजनीति का मूलमंत्र विकास है और इसीलिए लोग मोदी जी के साथ हैं।

— **प्रकाश जावडेकर**, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री

यह हमारे लिए खुशी की बात है। यह विकास की जीत है। जो जीता वही सिकंदर। यह सभी बूथ कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम और जो लोग विकास पर विश्वास करते हैं, उनकी जीत है।

— **स्मृति ईरानी**, केंद्रीय वस्त्र मंत्री

गुजरात की जनता ने लगातार छठी बार भाजपा नेतृत्व में जो आस्था और विश्वास व्यक्त किया है उससे साबित हो गया है कि आज देश में इसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश की जीत ने सिद्ध कर दिया है कि भारत कांग्रेस मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

— **वसुंधरा राजे**, मुख्यमंत्री, राजस्थान

गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों ने एक बार फिर संकेत दे दिया है कि नकारात्मक राजनीति से उबरकर विकास के प्रति रचनात्मक दृष्टि लेकर चलने की आवश्यकता है। यह देश सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है।

— **योगी आदित्यनाथ**, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी का अभिनन्दन!

— **शिवराज सिंह चौहान**, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

नतीजों ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि 2019 में होने वाले लोकसभा के आम चुनाव में एक बार फिर भारी बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी।

— **डॉ. रमन सिंह**, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

यह जनादेश पार्टी की 'विश्वास' एवं 'विकास' की राजनीति के लिए है। भाजपा गुजरात के लिए विश्वास और विकास की राजनीति के साथ सामने आई और लोगों ने उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। विपक्ष ने हमारे खिलाफ गलत संदेश फैलाने की कोशिश की।

— **देवेंद्र फडणवीस**, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

गुजरात व हिमाचल के चुनाव परिणाम से यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा 2019 के लोकसभा चुनावों में जीतने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने वाले राहुल गांधी अपनी शुरुआती पारी में शून्य पर आउट हो चुके हैं।

— **मनोहर पर्रिकर**, मुख्यमंत्री, गोवा

दोनों राज्यों में भाजपा की जीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा भारत वर्ष को दिया जानेवाला पवित्र शासन और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी की कुशल रणनीति है।

— **त्रिवेंद्र सिंह रावत**, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

गुजरात व हिमाचल दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। वर्ष 2014 में देश में हमारी सरकार भारी बहुमत से आई थी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है तथा अमित शाह जी के प्रयासों से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी का नेतृत्व हमें प्रेरणा दे रहा है।

— **मनोहर लाल खट्टर**, मुख्यमंत्री, हरियाणा

गुजरात में जीत का दावा करने वाली कांग्रेस हिमाचल प्रदेश भी हार गई। दोनों राज्य के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई!

— **नीतीश कुमार**, मुख्यमंत्री, बिहार

विकास ही देश का मंत्र है, विकास की ही जीत होगी: नरेन्द्र मोदी

गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विकास ही देश का मंत्र है और विकास की ही जीत होगी। लोगों में विकास की भूख जगी है, सरकारों की प्राथमिकता बनी है, इस विकास को पटरी से उतारने की हरकतें कृपा करके मत कीजिए।

प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में लगातार चुनाव आते रहते हैं, हर चुनाव को एक नए रंग रूप से रंगा जाता है। सच्चाई ये है कि 2014 मई में लोकसभा चुनाव के बाद इस देश में विकास का एक माहौल बना है। विकास की भूख जगी है। सरकारों की प्राथमिकता बनी है। ऐसे में भाजपा आपको पसंद हो या न हो, लेकिन देश को विकास के रास्ते से पटरी से उतारने (डिरेल) की हरकतें कृपा करके मत कीजिए।

उन्होंने कहा कि जिस दिन भाजपा हार जाए, महीने भर जश्न मनाइए, देश का नुकसान नहीं होगा। पर देश जब विकास के मंत्र को लेकर साथ आगे बढ़ रहा है, तो कहूंगा कि अवसर आया है कि एक ऐसी सरकार है जिसमें फैसले लेने की ताकत है। ऐसी सरकार है जिसकी नीयत साफ है, एक ऐसी सरकार है जो सामूहिक नेतृत्व और सहकारी संघवाद की भावना के साथ चलती है। एक ऐसी सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ काम करती है।

श्री मोदी ने कहा कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सत्ता के भूख के कारण इस चुनाव में कुछ लोगों ने न जाने कैसे कैसे प्रयास किये। 30 साल पहले जातिवाद का जहर इतना जेहन में डाल दिया गया था, उसको निकालते-निकालते मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के 30 साल खप गए, तब जाकर वो जातिवाद निकला।

उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और विकास की दिशा में चलें, जहां हैं वहां से आगे चलें, कुछ बाकी है तो उसे पूरा करें, इसी भाव से चलें। लेकिन सत्ता भूख के कारण इस चुनाव में कुछ लोगों ने, मैं किसी की आलोचना करने नहीं आया हूं, पर गुजरात को कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीने में फिर से जातिवाद के बीज बोने के प्रयास हुए हैं, जिसे गुजरात की जनता ने नकार दिया है, पर गुजरात की जनता को पहले से ज्यादा जागरुक होना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं गुजरात के लोगों से इस विजय के बाद भी कहने का साहस कर रहा हूं कि मेरे प्यारे गुजरात के लोग, साढ़े 6 करोड़ गुजराती एक हैं, नेक हैं। आगे बढ़ने का विश्वास लेकर चलने वाले हैं, जो हुआ, उसे छोड़ दो, किसने किया उसे भूल जाओ, फिर से एकता के बंधन में बंध जाएं।

उन्होंने कहा कि एक भी भाई हमसे अलग नहीं हो सकता है। एक भी गुजराती हमसे अलग नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने खेल खेले। वे अपनी हरकतें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए एकता का मंत्र लेकर सभी समाज से मिलकर चलें। गुजरात अकेला नहीं है। उसके विकास से देश को लाभ मिलता है। देश के लिए राज्यों का विकास आवश्यक है और गुजरात जैसे राज्यों की जिम्मेदारी ज्यादा है। ■

यह वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर विकासवाद की जीत है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 18 दिसंबर को भाजपा के केन्द्रीय मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली अभूतपूर्व जीत के लिए दोनों राज्यों की जनता का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता को अपनी ओर से और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हृदयपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की विकास यात्रा में अपना पूर्ण भरोसा जताते हुए एक बार फिर से हमें सेवा करने का मौक़ा दिया।

श्री शाह ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में जीत भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम की जीत है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गरीब-कल्याण की नीति की जीत है। उन्होंने कहा कि यह जीत वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर विकासवाद की जीत है, पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस की जीत है। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही देश के लोकतंत्र पर दुष्प्रभाव डालने वाले तीन नासूरों जातिवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण को देश की राजनीति से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया है कि देश का लोकतंत्र इन तीनों दुष्प्रभावों को ख़त्म कर पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस के एक नये युग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि अब यह सिद्ध हो चुका है कि जो परफॉर्म करेगा, जो विकास करेगा और जो जन-आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा, उसे ही लोकतंत्र में जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के 70 साल बाद हमारा लोकतंत्र करवट बदल रहा और विकास के युग में प्रवेश कर रहा है, इसका संपूर्ण श्रेय देश की जनता को जाता है और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को जाता है जो मोदी जी के नेतृत्व में अहर्निश परिश्रम कर रहे हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जहां तक गुजरात का सवाल है, 1990 के बाद से भाजपा गुजरात में कभी नहीं हारी, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो या लोक सभा चुनाव। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार छठी बार गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि 2012 के मुकाबले हमारे वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है, 2012 में भारतीय जनता पार्टी को 47.85% वोट मिला था, इस बार अभी तक के परिणामों के अनुसार हमें 49.10% वोट मिले हैं, जो पिछले बार की तुलना में 1.25% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुजरात की जनता के अटूट विश्वास को प्रदर्शित करता है।

श्री शाह ने कहा कि गुजरात चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी द्वारा मुद्दों को भटका कर पूरे चुनाव को जातिवाद की दिशा में ले जाने

का प्रयास किया गया, गुजरात को जिस तरह से जातिवाद की आग में झोंकने का प्रयास किया गया, उसे गुजरात की जनता ने विफल कर दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव में भ्रांतियां फैला कर मुद्दों से भटकाने का जो प्रयास हुआ, उसका नतीजा यह आया है कि कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता चुनाव हार गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आउटसोर्सिंग के जरिये गुजरात चुनाव लड़ा था, यह इसी का परिणाम है कि गुजरात की जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास दिखाया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रचार के दौरान कांग्रेस द्वारा हर बार प्रचार का स्तर नीचे ले जाने का प्रयास हुआ, अलग-अलग प्रकार की अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, जातिवाद को भड़काने का भी प्रयास हुआ लेकिन गुजरात की जनता ने मोदी जी की पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस में अपना भरोसा दिखाते हुए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौक़ा दिया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हम बहुत बड़े अंतर से जीते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, हमें 2012 में 38.47% वोट मिले थे, इस बार हमें 48.6% वोट प्राप्त हुए हैं, अर्थात् भाजपा के वोट शेयर में पिछले बार की तुलना में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है और दो-तिहाई बहुमत से हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने मोदी जी के हिमाचल के साथ अटूट रिश्ते को और मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी में अपनी श्रद्धा जताई है। उन्होंने कहा की चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की विकास यात्रा में जुड़ना चाहता है।

श्री शाह ने कहा कि जहां तक राजनीतिक नतीजों का सवाल है, केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद देश में जितने भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपनी स्थिति को बेहतर किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में पांच राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और एक राज्य में भाजपा शासन में भागीदार थी, जबकि आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम आ जाने के बाद देश के 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और पांच राज्यों में भाजपा सहयोगियों के साथ मिल कर जनता की सेवा कर रही है, कुल मिलाकर देश के 19 राज्यों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें बनी हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देश के गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं के उत्थान के लिए 106 से अधिक योजनायें लेकर आई है और उसी का परिणाम है कि सारी योजनायें नीचे तक पहुंच कर इतने बड़े जन-समर्थन में तब्दील हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का अर्थतंत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे दुनिया की तमाम आर्थिक एजेंसियां इसको सत्यापित कर चुकी है।

श्री शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और कर्नाटक - चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में इन चारों राज्यों में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, इसके लिए भाजपा के कार्यकर्ता कटिबद्ध हैं, संकल्पवान हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोक सभा चुनाव में उतरेगी, तो देश भर में एक बार फिर से हमें जनसमर्थन प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, साथ ही प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के सामने 2022 तक न्यू इंडिया का जो लक्ष्य रखा है, इसे भी हम प्राप्त करने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं व भाजपा के कई प्रमुख नेताओं ने इन चुनावों में बिना थके हुए निरंतर परिश्रम किया हैं। मैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर से गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि देश की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देती रहेगी और हम जनता के इस आशीर्वाद को विकास में तब्दील कर देश को आगे बढ़ाने एवं न्यू इंडिया की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास करते रहेंगे। ■

भाजपा ने महाराष्ट्र में 10 स्थानीय निकायों में 6 पर जीत दर्ज की

भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में 10 में छह पर जीत दर्ज की और सर्वाधिक संख्या में उसके पार्षद निर्वाचित हुए। भारतीय जनता पार्टी, महाष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री रावसाहेब दानवे ने एक बयान में कहा कि सात नगरपालिका परिषदों-नगर पंचायतों के नतीजों के मुताबिक भाजपा ने औरंगाबाद, नांदेड़, धुले, कोल्हापुर और गोंदिया में अध्यक्ष पद जीता है। उन्होंने कहा कि सात नगरपालिका परिषदों-नगर पंचायतों में पार्षदों की कुल 123 सीटों में भाजपा ने 50 जीते हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती दो चरणों के नतीजों के मुताबिक भाजपा ने 10 में

छह नगरपालिका परिषदों और पार्षदों के 75 पदों पर जीत हासिल की है। ■

आईएनएस कलवरी राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 दिसम्बर को नौसेना गोदी, मुम्बई में आयोजित एक शानदार समारोह में आईएनएस कलवरी (एस-21) का जलावतरण किया। भारतीय नौसेना में परियोजना 75 (कलवरी श्रेणी) के अन्तर्गत निर्मित 6 स्कॉरपीन श्रेणी की पनडुब्बियों में से यह पहली पनडुब्बी है। फ्रांसीसी निर्माता मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डॉक लिमिटेड में निर्मित होने वाली 6 पनडुब्बियों में से इस पहली पनडुब्बी को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया।

इस ऐतिहासिक और युगांतरकारी घटना के अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री विद्या सागर राव, मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फणनवीस, रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, रक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष भामरे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत कुमार डोभाल, नौ सेनाध्यक्ष एडमिरल सुनील लाम्बा और अनेक अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

इस अवसर पर भारत की जनता को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने आईएनएस कलवरी को मेक इन इंडिया का एक प्रमुख उदाहरण बताया। उन्होंने इसके निर्माण में शामिल लोगों की सराहना की। उन्होंने पनडुब्बी को भारत और फ्रांस के बीच तेजी से बढ़ती हुई साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि आईएनएस कलवरी भारतीय नौसेना को और अधिक ताकत प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह निश्चित है कि 21वीं सदी में विकास का मार्ग हिंद महासागर से होकर गुजरेगा। इसीलिए सरकार की नीतियों में हिंद महासागर का विशेष स्थान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कल्पना को सागर-क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास से समझा जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हिंद महासागर में अपने वैश्विक, रणनीतिक और आर्थिक हितों के प्रति पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने कहा, यही कारण है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में आधुनिक और बहुआयामी भारतीय नौसेना प्रमुख भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि महासागरों की सहज संभावना हमारे राष्ट्रीय विकास की आर्थिक शक्ति बढ़ाती है। यही कारण है कि भारत को समुद्र के रास्ते आतंकवाद, डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी चुनौतियों की भली-भांति जानकारी है, न केवल भारत को बल्कि क्षेत्र के अन्य देशों को भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इन चुनौतियों से निपटने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, भारत का मानना है कि विश्व एक परिवार है और अपनी वैश्विक जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। भारत ने संकट के समय अपने सहयोगी देशों के लिए सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारतीय कूटनीति और भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठान का मानवीय चेहरा हमारी खासियत है। उन्होंने कहा कि एक

मजबूत और सक्षम भारत को मानवीयता के लिए एक प्रमुख भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के देश शांति और स्थिरता के रास्ते पर भारत के साथ चलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी समूची प्रणाली में परिवर्तन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आईएनएस कलवरी के निर्माण के दौरान जिस कौशल का इस्तेमाल किया गया वह भारत के लिए एक पूंजी है।

अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि एक रैंक एक पेंशन का लम्बित मामला हल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों और सशस्त्र बलों की बहादुरी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि जम्मू-कश्मीर में छद्म युद्ध के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल सफल नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया।

एक बार फिर पनडुब्बियों का उत्पादन दोबारा शुरू करने के लिए एमडीएल को बधाई देते हुए रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यार्ड कर्मियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज के दिन उनका काफी महत्व है। उन्होंने कहा कि पनडुब्बी निर्माण की प्रक्रिया देश में एक बार फिर शुरू हो चुकी है और इसे रुकना नहीं चाहिए। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि उद्योग में अनियमित शुरुआत और रूकावट से बचने और देश के भीतर उच्च प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के निर्माण के लिए कौशल का एक पूल बनाये रखने की आवश्यकता है। इसे बनाये रखने से भारतीय उद्योग की बेहतरी होगी, कौशल को बनाये रखा जा सकेगा।

उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि यह जलावतरण देश में पनडुब्बी के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर है। भारतीय नौसेना देश में निर्माण के सिद्धान्त और सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध है। कलवरी का जलावतरण हमारे इस संकल्प का गवाह है और यह उपलब्धियां आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारतीय नौसेना के अति सक्रिय और समेकित दृष्टिकोण का परिणाम है। ■

मंत्रिमंडल ने 2000 रुपये मूल्य तक के डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/एईपीएस के लेन-देन पर लागू एमडीआर शुल्क की भरपाई करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2000 रुपये मूल्य तक के सभी डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) लेन-देन पर लागू मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) दो वर्ष की अवधि के लिए सरकार द्वारा वहन करने की मंजूरी दी। यह 01 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगा और इसकी बैंकों को अदायगी की जाएगी।

वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव, इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के सीईओ को मिलाकर बनाई गई एक समिति ऐसे लेन-देन के औद्योगिक खर्च ढांचे को देखेगी, जिससे अदायगी के स्तरों का पता लगाने का आधार तैयार किया जाएगा।

इस मंजूरी के परिणामस्वरूप 2000 रुपये से कम मूल्य के किसी भी लेन-देन के लिए उपभोक्ता और व्यापारी को एमडीआर के रूप में इस तरह के अतिरिक्त बोझ से परेशान नहीं होना पड़ेगा। इससे इस प्रकार के लेन-देन के लिए डिजिटल भुगतान मोड को लोग अधिक अपनाएंगे। चूंकि इस तरह के लेन-देन का प्रतिशत काफी अधिक है, इससे कम नकदी की अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने में मदद मिलेगी।

अनुमान लगाया गया है कि 2000 रुपये से कम मूल्य वाले

लेन-देन के संबंध में बैंकों को वित्त वर्ष 2018-19 में 630 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019-20 में 883 करोड़ रुपये की एमडीआर अदायगी की जाएगी। बिक्री के व्यापारी पीओएस पर जब भुगतान किया जाता है, एमडीआर की अदायगी व्यापारी द्वारा बैंक को की जाती है, इसे देखते हुए अनेक लोग डेबिट कार्ड रखने के बजाय नकद भुगतान करते है। इसी प्रकार से भीम यूपीआई प्लेटफॉर्म और एईपीएस के जरिये व्यापारियों को किये गये भुगतान पर एमडीआर चार्ज किया जाता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 30 करोड़ से भी अधिक खाते खोले गए

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत 06 दिसंबर, 2017 तक कुल मिलाकर 30.71 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें से 18.05 करोड़ खाते ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। विभिन्न बैंक अपनी-अपनी शाखाओं में उन व्यक्तियों के पीएमजेडीवाई खाते खोल रहे हैं, जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं। पीएमजेडीवाई खाते खोलने की सुविधा प्राप्त बैंक मित्रों को इस कार्य के लिए तैनात किया गया है। बैंक मित्र 1000-1500 परिवारों वाले उन उप-सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में खाते पहले से खोल रहे हैं, जिन्हें अब तक कवर नहीं किया जा सका है।

राजस्व विभाग ने यह जानकारी दी है कि 8 नवम्बर, 2016 से लेकर 30 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान 3,74,14,844 पीएमजेडीवाई खातों में 42,187 करोड़ रुपये जमा कराए गए थे। राजस्व विभाग को इस बारे में जानकारी 187 रिपोर्टिंग निकायों ने दी है। ज्यादा जोखिम वाले मामलों की पहचान करने, संदिग्ध मामलों के

त्वरित सत्यापन और आवश्यकता पड़ने पर प्रवर्तन कर्रवाई के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। नकद लेन-देन से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना, इस तरह की सूचनाओं का विश्लेषण करना और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं डेटा विश्लेषणात्मक उपकरणों (टूल) का व्यापक उपयोग करना इन कदमों में शामिल हैं।

आइज़ोल की तुरिअल पन-बिजली परियोजना राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 दिसंबर को मिजोरम के आइज़ोल में 60 मेगावॉट की तुरिअल जलविद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया। दरअसल, तुरिअल जलविद्युत परियोजना का निर्माण केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में किया गया है। इसका क्रियान्यवन विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन (नीपको) द्वारा किया गया। गौरतलब है कि आर्थिक मामलों पर मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीईए) ने जुलाई 1998 में परियोजना के क्रियान्यवन को अनुमति प्रदान की थी और जुलाई 2006 में इसके पूरा होने का समय निर्धारित किया था। जून, 2004 में परियोजना का तीस प्रतिशत कार्य पूरा होने के बाद स्थानीय आंदोलन के कारण काम को पूर्ण रूप से रोकना पड़ा। निपको के सतत प्रयासों और विद्युत तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, केंद्र और मिजोरम सरकार के सक्रिय सहयोग से जनवरी, 2011 में परियोजना में फिर से काम की शुरुआत हुई।

परियोजना में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनमें दुर्गम क्षेत्र, दूरसंचार के आधारभूत ढांचे की कमी, मिट्टी की कमजोर स्थिति के कारण पावर हाउस का बड़ा स्तर पर सफल न होना और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध न होना आदि प्रमुख थी। इसके कारण परियोजना को पूरा करने में अधिक समय लगा, लेकिन सभी संबधित एंजेसियों के प्रयासों के चलते परियोजना का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ और 25-8-2017 को पहली इकाई और 28-11-2017 को दूसरी इकाई की शुरुआत हुई।

इस परियोजना का क्रियान्वयन नीपको द्वारा किया गया। इसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा ऊर्जा उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना, मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग द्वारा प्रमुख भूमि कार्य और मैसर्स सो-पीईएस-तुरिअल कंसोर्टियम द्वारा जल-यांत्रिकी कार्य किया गया। परियोजना का निर्माण 1302 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

यह परियोजना मिजोरम में स्थापित सबसे बड़ी परियोजना है और इससे उत्पादित बिजली राज्य को दी जाएगी। इससे राज्य का संपूर्ण विकास और केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी और प्रमुख कार्यक्रम "सभी को सातों दिन चौबीसों घंटे किफायती स्वच्छ ऊर्जा" के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सकेगा।

राज्य में बिजली की मौजूदा मांग केवल 87 मेगावाट है और इसकी पूर्ति राज्य की लघु बिजली परियोजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में उसके अपने हिस्से की बिजली की उपलब्धता के जरिए हो रही है। परियोजना से अतिरिक्त 60 मेगावाट बिजली प्राप्त होने के साथ ही मिजोरम राज्य अब सिक्किम और त्रिपुरा के बाद पूर्वोत्तर भारत का तीसरा विद्युत-अधिशेष राज्य बन जाएगा। बिजली में आत्मनिर्भरता हासिल करने के अलावा इस परियोजना से मिजोरम राज्य को कुछ अतिरिक्त लाभ हासिल होंगे, जिनमें रोजगार सृजन, नौवहन, जलापूर्ति, मत्स्य पालन एवं वन्य जीव-जंतु का संरक्षण, पर्यटन, इत्यादि शामिल हैं।

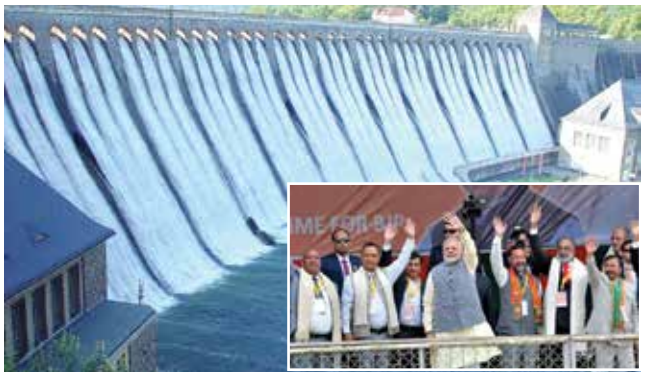

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास को लेकर अटल जी के कार्यकाल में बहुत गंभीर प्रयास हुए थे। अटल जी कहते थे आर्थिक सुधार का एक बड़ा मकसद है क्षेत्रीय भेदभाव को पूरी तरह खत्म करना। इस दिशा में उन्होंने काफी कदम भी उठाए थे।

उन्होंने कहा कि 2014 में हमारी सरकार बनी तो एक बार फिर इस क्षेत्र को, हम सरकार की नीतियों और फैसलों में आगे लेकर आए हैं। मैंने तो एक नियम बना दिया था कि हर 15 दिन में कैबिनेट का कोई ना कोई मंत्री उत्तर पूर्व के राज्यों का दौरा जरूर करेगा। ये भी नहीं होगा कि सुबह आए, दिन में किसी इवेंट में हिस्सा लिया और शाम को वापस चला जाए। मैं चाहता था कि मंत्रिमंडल के मेरे साथी यहां रुककर, आपके बीच रहकर आपकी आवश्यकताओं को समझें, उनके मुताबिक अपने मंत्रालयों में नीतियां बनाएं।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में मेरे साथी मंत्रियों की 150 से ज्यादा विजिट उत्तर पूर्व के राज्यों में हो चुकी है। हम इस विजन के साथ काम कर रहे हैं कि अपनी परेशानियां, अपनी आवश्यकताएं बताने के लिए आपको दिल्ली तक संदेश ना भिजवाना पड़े, बल्कि दिल्ली खुद आपके बीच चलकर आए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी हमारे देश में ऐसे 4 करोड़ घर हैं, जिनमें अब तक बिजली का कनेक्शन नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग किस तरह 18वीं सदी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। यहां मिजोरम में भी हजारों घर ऐसे हैं, जो अब भी अंधकार में जिन्दगी गुजार रहे हैं। ऐसे घरों में बिजली पहुंचाने के लिए सरकार ने हाल ही में 'प्रधानमंत्री सहज बिजली- हर घर' योजना यानी 'सौभाग्य' की शुरुआत की है। हमारा लक्ष्य है जल्द से जल्द देश के हर घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ा जाए।

उन्होंने कहा कि इस योजना पर लगभग 16 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। जिन गरीबों को इस योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, उनसे कनेक्शन के लिए सरकार कोई पैसा नहीं वसूलेगी। हम चाहते हैं कि गरीबों की जिंदगी में उजाला आए, उनकी जिंदगी रोशन हो। ■

सामाजिक रचना का आधार

| दीनदयाल उपाध्याय |

पिछली बार जब हमने कुछ विचार किया था तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कार्य का आधार धर्म होना चाहिए। हम जिस वैभव की प्राप्ति करना चाहते हैं, वह धर्मयुक्त होना चाहिए। जिससे धारणा होती है, वह धर्म होना चाहिए। व्यक्ति और समाज जिन सिद्धांतों के आधार पर उन्नति करें, वह धर्म होना चाहिए। व्यक्ति की सब क्रियाएं क्यों हैं? क्यों रोटी खाते हैं? हम सब पेट के लिए रोटी खाते हैं। कहीं रोटी खाते हैं, कहीं अच्छी पूरियां खाते हैं। एक ठाकुर नाई को साथ लेकर ससुराल गए। रास्ते में स्वयं ने तो कचौरी खाई और नाई को पैसे दिए कि जाकर चने खा ले। ससुराल में पहुंचकर नाई ने वहां के लोगों से कह दिया कि ठाकुर साहब का पेट खराब है। वे केवल मूंग की दाल ही खाएंगे। अब दो-तीन दिन तक मूंग की दाल ही उन्हें खिलाई गई। इस तरह नाई ने अपना बदला ले लिया। व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, लेकिन आज का सुख कल का दुःख भी तो हो सकता है। आज कुल्फी खाई, कल गला भी खराब हो सकता है। लोग कल के सुख के लिए आज दुःख भी उठाते हैं। मसूरी का सुख ध्यान में रखकर लोग वहां की घुमावदार सड़कों पर चलते हुए उल्टियां करते हैं, लेकिन मसूरी की कल्पना उनके मन में होती है। इसलिए वह दुःख बरदाश्त हो जाता है। स्थायित्व का बहुत महत्त्व होता है। दालरोटी को हम अपना मानते हैं। लेकिन जहां पकवान मिलें और साथ में तिरस्कार भी हो तो वह पकवान किस काम का? भगवान् कृष्ण ने दुर्योधन की मेवा छोड़कर विदुर के घर साग क्यों खाया? सुख केवल शरीर का ही नहीं होता, सुख तो मन का होता है। मन में दुःख हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता।

एक बार लोग भोजन कर रहे थे। तभी तार आया कि रेलगाड़ी की टक्कर में किसी की मृत्यु हो गई है। वे अभी-अभी सुख का अनुभव कर रहे थे, एकदम से दुःख का समाचार मिला तो अच्छा न लगा। लोग होटल का खाना छोड़कर माता के हाथ का बना भोजन क्यों पसंद करते हैं' क्योंकि उसमें मन का सुख मिलता है। भीम कितना खाना खाते थे, लेकिन जब तक मां कुंती के हाथ से एक-दो निवाले न खा लें, उन्हें सुख नहीं मिलता था, उनकी भूख ही नहीं मिटती थी। हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाए तो बुद्धि का भी सुख प्राप्त हो जाता है। शरीर और मन से परे आत्मा का सुख होता है। सुंदर फूल देखकर आनंद और मुरदे को देखकर दुःख क्यों प्राप्त होता है? एक बार कहीं आग लग गई। बच्चा अंदर ही रह गया। उसकी मां छटपटा रही थी। एक नौजवान बच्चे को निकाल लाया शरीर को कुछ नुक़सान हुआ, लेकिन फिर भी उसे सुख प्राप्त हुआ। बच्चे को बचाने की भावना से उसे आत्मिक सुख प्राप्त हुआ।

सुख चार प्रकार के होते हैं- भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक। जो रास्ता हमें इन चारों सुखों से मिला दे, वही धर्म का रास्ता है। अंदर और बाहर के जो सुख हैं, यानी भौतिक और आध्यात्मिक जो सुख हैं, ये धर्म के हैं। इसलिए दोनों में से एक की भी अवहेलना हमें नहीं करनी है जो एक की उपासना करता है, वह गलत है। रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं चाहिए, हमें आत्मिक सुख भी चाहिए। अपनी दृष्टि बिगाड़कर हमें रोटी नहीं चाहिए। सम्मानपूर्वक मिलनी चाहिए। रहीम ने एक जगह कहा है, पेट तू पीठ होना चाहिए था। क्योंकि यदि भर जाता है तो दृष्टि बिगाड़ता है, यानी गलत कार्मों को उकसाता है और यदि खाली रहता है तो ठीक रहता है। अभ्युदय और निश्रेयस्य दोनों की प्राप्ति जिससे हो, वह धर्म केवल एक नहीं है। उस धर्म को प्राप्त करने का विचार, उस सुख को प्राप्त करने का विचार केवल व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। काम करके, परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके, कर्मयोग द्वारा ही यह सुख प्राप्त हो सकता है।

कर्म का सिद्धांत हमारे यहां विशेष है। एक और विशेष चीज़ है 'कमाने वाला खाएगा'। इस विचार को मान्यता नहीं दी गई है। यह बात तो अच्छी है, लेकिन सभी जानते हैं कि कल न कमाने का काल भी तो आ सकता है बचपन था तब भी कमाते नहीं थे, किंतु आज कमाएंगे हम और खाएगा कोई और, यह प्रकृति नहीं है। प्रकृति के ऊपर भी एक चीज़ है संस्कृति। कमाने वाले खिलाएंगे-यही हमारे यहां का सिद्धांत है। प्रकृति में यही है कि जो जैसा कर्म करेगा, वैसा फल

पाएगा, हम दूसरों के लिए कर्म करेंगे-यही हमारा यज्ञ है। यह यज्ञ धर्म संस्कृति का आधार है। वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता। वह अपने सपूर्ण जीवन रस को फल में रख देता है, वह तो पत्थर मारने वाले को भी फल देता है। नदियां अपना सारा पानी खुद ही पीने लग जाएं वृक्ष अपने फल खुद ही खाने लग जाएं तो दूसरों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। सृष्टि का चक्र ही रुक जाएगा। सबका आधार कर्म है।

कर्म यज्ञमय है। यज्ञ कर्म हमारी ब्रह्ममयी भावना से है, जिसमें से एकात्मता पैदा होती है। पेड़, गाय, चंडाल, ब्राह्मण-सभी में इसका दिग्दर्शन करता है। मां-बेटे में अपना। स्वरूप देखकर, उसे अपना समझकर सुख मानती है। हमारे यहां समानता का नहीं, आत्मीयता का सिद्धांत है। संपूर्ण विश्व के अंदर एकात्मकता का भाव रहता है। फिर प्रत्येक काम में सुसूत्रता आती है। कुटुंब का आधार समानता नहीं, एकात्मता है। विद्या, आयु, भौतिक सामर्थ्य, खाने-पीने किसी में समान नहीं। कुटुंब में समानता केवल छोटी सी बात की है। वह है एक ही कुटुंब की, गोत्र आदि की। पश्चिम ने समानता का नारा दिया। वह बस जेल में है, प्रत्येक करेगा अपनी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक पाएगा अपनी आवश्यकता के अनुसार, निर्णय कौन करेगा कि किस की कितनी क्षमता है तथा कितनी आवश्यकता है, जहां पर हरेक ने सोचा कि मैं ही क्यों काम करूं' एक कुटुंब में एक भाई अच्छा एथलीट था, काम नहीं करता था घर में चाय नहीं बनी थी। भाभी ने कहा, 'कमाओ'। भाई भी घर में आकर बैठ गया। उसने शतरंज खेलना प्रारंभ कर दिया। तीसरे ने कविता लिखनी शुरू की, धीरे-धीरे घर खत्म होने लगा। घर तब ही चल सकता है, जब ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए और कम से कम उसमें से लिया जाए।

घर में आत्मीयता होगी, तभी ऐसा हो सकता है। मां तभी सवेरे से काम शुरू करती है। रात्रि तक काम में लगी रहती है। क्या खाती है? बच्चे को खिलौना चाहिए। सबके अंदर का साम्य भाव चाहिए फिर अंदर से यज्ञ भाव उत्पन्न होता है। राजा को प्रजा के लिए और प्रजा को राजा के लिए सोचना चाहिए। पति-पत्नी के लिए और पत्नी-पति के लिए सोचे। इसी भावना से समाज की रचना हो सकती है और सृष्टि भी इसी आधार पर खड़ी है। हमारे यहां पुनर्जन्म मे विश्वास किया जाता है लोग कहते हैं अगले जन्म में यह कर्म साथ-साथ जाएगा। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम अकेले नहीं हो, सृष्टि के साथ बंधे हो। अकेले को आनंद नहीं आ सकता। रोटी हमारे अकेले के लिए नहीं है। उसके लिए बहुत लोगों को काम करना पड़ता है। इसी तरह कपड़ा बनाया जाता है। हमारा सारा जीवन दूसरे पर अवलंबित है। केवल हमारे समाज पर ही नहीं पूरी सृष्टि पर हमारा जीवन अवलंबित है तूफान, आंधी, वर्षा के लिए भी हम दूसरों पर निर्भर हैं।

सारे सुखों के साथ-साथ मानसिक सुख भी हमारे लिए जरूरी है एक बार एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी लाकर दी। सुबह उसकी अंगूठी की तरफ़ किसी का भी ध्यान नहीं गया। वह बहुत परेशान थी कि कोई उसकी अंगूठी देखे और तारीफ करे, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ़ ध्यान नहीं दिया। उस स्त्री ने अपने घर में आग, लगा दी। जब सब लोग आग बुझाने आए तो वह अंगूठी वाले हाथ से इशारा कर करके

बताती रही कि पानी इधर डालो, उधर डालो। अचानक किसी का ध्यान उसकी अंगूठी पर गया। उसने तारीफ की और पूछा कि कहां से लाई। वह एकदम बोल उठी कि अगर किसी ने पहले ही पूछ लिया होता तो घर में आग तो न लगती। इसी तरह एक और कहानी है कि किसी नाई ने राजा का कटा हुआ कान देख लिया था। राजा ने उसे मना किया कि यह बात किसी और को न बताए। बताने पर उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन नाई को वह बात हजम नहीं हो पा रही थी। उसके कारण उसका पेट फूल गया था। वह किसी इलाज से ठीक नहीं हुआ। किसी साधू के बताने पर उसने अपनी बात जंगल में जाकर एक बांस के पेड़ को बताई। तब जाकर उसका पेट फूलना बंद हुआ। इसी तरह सारे सुखों के साथ-साथ मानसिक सुख भी आवश्यक है। व्यक्ति का सृष्टि की सत्ता के साथ-साथ जहां ताल-मेल बैठे, उसी में से सेवा, यज्ञ, त्याग की वृत्ति पैदा होती है। यही धर्म है। चारों पुरुषार्थ-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-जितनी पद्धतियां चारों सुखों की हैं, वे इसके अंतर्गत आती हैं। व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि इन चारों सत्ताओं में एकात्मता है।

व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, लेकिन आज का सुख कल का दुःख भी तो हो सकता है। आज कुल्फी खाई, कल गला भी खराब हो सकता है। लोग कल के सुख के लिए आज दुःख भी उठाते हैं। मसूरी का सुख ध्यान में रखकर लोग वहां की घुमावदार सड़कों पर चलते हुए उल्टियां करते हैं, लेकिन मसूरी की कल्पना उनके मन में होती है। इसलिए वह दुःख बरदाश्त हो जाता है। स्थायित्व का बहुत महत्त्व होता है। दालरोटी को हम अपना मानते हैं, लेकिन जहां पकवान मिलें और साथ में तिरस्कार भी हो तो वह पकवान किस काम का?

कर्म, पुनर्जन्म सबके अंदर एक ही सत्य है- ब्रह्म। एकोहम् द्वितीयो नास्ति, यज्ञ की उस एकात्मता के आधार पर हमारा धर्म टिका है। चतुर्सूत्री के आधार पर हमारे समाज की रचना हुई। ■

(-जून 13, 1958 में संघ शिक्षा वर्ग में दिये गये बौद्धिक का पाठ)

स्वामी विवेकानंद

(12 जनवरी 1863 - 4 जुलाई 1902)

स्वामी विवेकानन्द का वास्तविक नाम नरेन्द्र नाथ दत्त था। वे वेदान्त के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म महासम्मेलन में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का वेदान्त अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। अपने मत से पूरे विश्व को हिला देने की शक्ति थी उनमें। वे श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सुयोग्य शिष्य थे।

स्वामी विवेकानन्द का जन्म 12 जनवरी, 1863 को कलकत्ता (कोलकता) में हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिता एक विचारक, अति उदार, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, धार्मिक व सामाजिक विषयों में व्यवहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। भुवनेश्वरी देवी सरल व अत्यंत धार्मिक महिला थीं ।

स्वामी जी 1893 में शिकागो (अमेरिका) में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। शिकागो में उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं, जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं, जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है।

वहां स्वामी जी ने कहा कि जिस तरह अलग-अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद में जाकर मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग-अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े-मेढ़े लगें, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं।

स्वामी जी जनवरी 1897 में अमेरिका से भारत वापस लौटे। अपने उत्साहपूर्व स्वागत के बीच उन्होंने देश के विभिन्न भागों में अनेक भाषण दिए, जिससे देश में एक नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव हुआ। स्वामी विवकानंद ने कहा कि जनता को दो तरह के ज्ञान की आवश्यकता है-सांसारिक ज्ञान, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा आध्यात्मिक ज्ञान, जिससे उनका आत्मविश्वास मजबूत हो। प्रश्न यह था कि इन दो प्रकार के ज्ञान का प्रसार कैसे हो। स्वामी जी ने इसका उत्तर शिक्षा के विकास में पाया।

एक बार भयंकर अकाल पड़ा। स्वामी विवेकानंद का हृदय पीड़ितों की सेवा के लिए भावविभोर हो उठा। वे दिन-रात सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते। उन दिनों कोई भी साधु-संत या पंडित धर्म या दर्शन पर चर्चा के लिए आते तो सारी चर्चा को बंद करके वे अकाल पीड़ितों की सेवा को ही बातचीत का मुख्य मुद्दा बना देते थे।

भारत की युवा शक्ति पर अटूट विश्वास

स्वामी विवेकानन्द भारत की युवा शक्ति पर अटूट विश्वास और आस्था रखते थे। उनके मानस-पटल पर भारत का स्वर्णिम अतीत अंकित तो था ही, साथ ही वे अपने युग की पराधीनता की पीड़ा तथा उसके परिणामस्वरूप घटित आर्थिक दुर्दशा, सामाजिक विघटन और सांस्कृतिक अधःपतन से भी चिन्तित थे। वे भारत के उज्जवल भविष्य के सपने संजो रखे थे। इसीलिए युवा पीढ़ी पर उन्हें बहुत भरोसा था।

उन्हें विश्वास था कि उनकी अनुगामी युवा पीढ़ी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण के उनके सन्देशों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर राष्ट्र-मुक्ति और सामाजिक-सांस्कृतिक नव जागरण के पुनीत अभियान को निरन्तर आगे बढ़ायेगी और भारत माता के प्रति अपने धर्म का पूरा पालन करेगी। उन्होंने कहा, 'भारत की युवा-शक्ति देशहित को सर्वोपरि मानकर त्याग और सेवा के प्रति अपने को समर्पित कर दे, लक्षावधि युवक अपनी सुख-सुविधाओं को त्याग कर, करोड़ों दीन-दुःखी-पीड़ित भाइयों के उत्थान-कार्यो में जुट जायें।'

जीवन के अन्तिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा- "एक और विवेकानन्द चाहिये, यह समझने के लिये कि इस विवेकानन्द ने अब तक क्या किया है।" जीवन के अन्तिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः दो तीन घण्टे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चन्दन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गयी। ■

स्वामी जी के प्रमुख कार्य

- लोगों में धार्मिक चेतना भरना तथा उनमें उनमें अपने सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व जागृति करना।
- हिंदू धर्म का विभिन्न संप्रदायों के बीच समान सिद्धांतों के आधार पर एकीकरण करना।
- शिक्षित लोगों का ध्यान पिछड़ी जनता की बदहाली पर केंद्रित करना तथा उनके विकास के लिए वेदांत के सिद्धांत को व्यवहार में लाना।

विश्वसनीयता और लोकप्रियता के एसिड टेस्ट में फिर खरे उतरे नरेंद्र मोदी

| प्रशांत मिश्र |

गुजरात और हिमाचल प्रदेश का नतीजा भी वही आया जो लोकसभा चुनाव के बाद से ज्यादातर दिखता रहा था। जनता ने भाजपा को ही सिर-आंखों पर बिठाया। गुजरात मॉडल बरकरार रह गया। चेहरा, मुद्दा और प्रबंधन के मापदंड पर भाजपा अन्य दलों की तुलना में जहां खड़ी है, उसमें आश्चर्य की बात भी नहीं है। यह फिर से स्थापित हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के प्रबंधन की काट विपक्ष के पास नहीं है।

लेकिन सवाल यह खड़ा हो गया है कि विपक्षी पार्टियां और खासकर कांग्रेस क्या जनता और जमीन के मूड का आकलन करने में पूरी तरह अक्षम हो गई है? यह सच है कि कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ी हैं, लेकिन क्या यह सचमुच में कांग्रेस के लिए संजीवनी है, खास तौर पर तब, जबकि इसका श्रेय गुजरात के कुछ युवा तुर्कों को दिया जा रहा है।

गुजरात विधानसभा चुनाव जाहिर तौर पर हाल के कुछ मुश्किल चुनावों में गिना जाएगा। कारण भी है- हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से अलग भाजपा उस गुजरात में चुनाव लड़ रही थी, जहां वह 22 वर्षों से सत्ता में थी। लंबे अरसे बाद मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं था। पाटीदार बिदके हुए थे और जीएसटी जैसे मुद्दों को हवा देकर कांग्रेस ने व्यापारियों की नाराजगी को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इससे इनकार करना संभव नहीं होगा कि खुद मोदी और शाह इन कारणों के असर को भी समझ रहे थे।

यही वजह थी कि दूसरी ओर से भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। खुद मोदी ने जहां लगभग ढाई दर्जन रैलियां कीं, वहीं बदजुबानी करने वाले मणिशंकर अय्यर से लेकर पाकिस्तान और अफजल तक हर मुद्दे को धार देने में कोई चूक नहीं हुई। अब युद्ध में तो सब कुछ जायज होता है और गुजरात चुनाव सियासी युद्ध से कम भी नहीं था।

राहुल गांधी ने अभी-अभी औपचारिक रूप से कांग्रेस की कमान संभाली है और हिमाचल के रूप में एक और राज्य हाथ से निकल गया। गुजरात के नतीजों ने मलहम का काम किया होगा और उधार के कंधों के सहारे ही सही यह कहने का अवसर भी दिया कि वह मोदी के गृह राज्य में भाजपा को टक्कर देने की स्थिति तक पहुंची। शायद यह भविष्य के लिए जोश जगाने में सफल हो और विपक्षी एकजुटता के लिए कुछ गोंद का काम भी करे। लेकिन यह सवाल बरकरार है कि मुद्दे और समीकरण अनुकूल होते हुए भी कांग्रेस सत्ता की दौड़ में पीछे छूट गई तो फिर आगे का रास्ता आसान कैसे माना जाए। ध्यान रहे कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अगले लंबे वक्त तक केंद्र में भाजपा सरकार का दावा कर रहे हैं। इसका कारण भी है और गुजरात चुनाव ने उसे पुष्ट भी किया है। कारण है जनता और कार्यकर्ता से कांग्रेस का कटाव व वर्तमान राजनीति की कम समझ।

कांग्रेस ने उस विकास को पागल करार दे दिया जो अब चुनावी मुद्दा बनने लगा है। जब तक बात समझ में आती और उसे वापस लेते, जनता ने दूरी बना ली। कांग्रेस में खुद की पार्टी और नेताओं पर भरोसे का आलम तो यह रहा कि तीन बाहरी युवाओं को सिर पर चढ़ा लिया और अपने बेगाने हो गए। ऐसे में कार्यकर्ता कितने सधेंगे यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी भूल तो यह हो गई कि राज्य में जिस कांग्रेस के पास 37-38 फीसदी वोट है, उसने भी खुद को नाजुक कर दिया। यानी अब किसी भी राज्य में कोई भी नया अपरिपक्व युवा कोई संवेदनशील मुद्दा लेकर खड़ा हो सकता है और दावा कर सकता है कि कांग्रेस उसकी मुट्ठी में है। सत्ता की हताशा में ऐसी राजनीति न तो जनता को पसंद है और न ही किसी भी पुराने कार्यकर्ता को रास आएगी।

हिमाचल प्रदेश तो और भी अनूठा उदाहरण है, जहां कांग्रेस लड़ ही नहीं रही थी। सही मायने में तो वीरभद्र सिंह के रूप में एक बागी मैदान में था जो कांग्रेस आलाकमान के आदेश-निर्देश से परे था। कांग्रेस उनकी जिद मानने को मजबूर थी। ज्यादा अहम यह है कि कांग्रेस क्या जनता की भावना और अपेक्षाओं से भी दूर है? हाल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत कुछ अन्य राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक को मुद्दा बनाया। मुंह की खानी पड़ी। विकास का मुद्दा वहां उठाया जो देश के तीन-चार विकसित राज्यों की सूची में है और जहां विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से ऊपर रही है।

हां, यह मानकर चलिए कि गुजरात में जिस तरह कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व को साधने की कोशिश की है वह आगे भी कायम रहेगी। यह और बात है कि इसके कारण विपक्षी गठजोड़ कितना बचेगा यह कहना भी मुश्किल है। आज राहुल सीना फाड़कर शिवभक्त होने का दावा जरूर कर लें, लेकिन यह भी सत्य है कि उनकी पार्टी की सरकार ने ही एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भगवान राम और रामसेतु ऐतिहासिक सत्य नहीं हैं। वाम दल और ममता बनर्जी सरीखी नेताओं को कांग्रेस का बदला हुआ चोला कितना रास आता है यह देखना भी रोचक होगा। ■

(दैनिक जागरण से साभार)

नए भारत के लिए जनादेश

भूपेंद्र यादव

परंपरागत भारतीय राजनीति में चुनाव जाति, वंश, संप्रदाय जैसे पहलुओं पर केंद्रित रहे हैं। तमाम चुनाव विश्लेषक भी इन्हीं आधार पर चुनावी भविष्यवाणी करते रहे हैं, परंतु भाजपा गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वंशवाद और जातिवाद के खिलाफ विकासवाद के नारे के साथ चुनावी रण में उतरी। कांग्रेस ने न केवल भाजपा की विकासवादी राजनीति का विरोध किया, बल्कि भ्रामक प्रचार के माध्यम से यह धारणा स्थापित करने का प्रयास भी किया कि गुजरात के विकास में सत्यता नहीं है। जहां कांग्रेस अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाई, वहीं भाजपा लगातार विकास के मुद्दे के साथ चुनाव में आगे बढ़ती रही। चुनाव के दौरान ही विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से भी गुजरात के विकास दर के दस प्रतिशत होने की बात सामने आई।

अगर गुजरात में विगत 22 वर्षों के भाजपा शासन को देखें तो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में गुजरात ने बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से विकास किया है। सरकार की नीतियों के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। केंद्र सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी के रूप में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कांग्रेस को लगा था कि वह नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों के सहारे गुजरात में जीत हासिल कर लेगी,

गुजरात में विगत 22 वर्षों के भाजपा शासन को देखें तो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में गुजरात ने बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से विकास किया है। सरकार की नीतियों के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। केंद्र सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी के रूप में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

मगर जनता ने उसकी मंशा भांपते हुए उसके इरादों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। अगर इस चुनाव का समग्र विश्लेषण करें तो इस चुनाव में विकास के मुद्दे और सरकार के प्रति जनता का विश्वास स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि गुजरात में विकास की जो प्रक्रिया चली है उसका लाभ गुजरात के सभी लोगों को मिला है। यहां तक कि कांग्रेस के समय जब रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी बताया गया था कि गुजरात में अल्पसंख्यकों का विकास अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर

ढंग से हुआ है। वैसे विकास का तात्पर्य सिर्फ सरकार की नीतियों से नहीं है। इसके अंतर्गत कई और विषय भी आते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति, महिलाओं का सम्मान, अधिकतम कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पारदर्शी ढंग से पहुंचाने की व्यवस्था, भ्रष्टाचार का खात्मा, निर्णायक नेतृत्व, ये सब भी विकास के मानक होते हैं जिनमें गुजरात की स्थिति बहुत बेहतर है।

विकास के अलावा गुजरात चुनाव का दूसरा केंद्र बिंदु सुशासन रहा। इस चुनाव समेत पहले भी कांग्रेस जब भी चुनाव लड़ी है, उसने वोट बैंक की राजनीति को ही प्रमुख माना है। वह दलित से लेकर अल्पसंख्यक तक सभी को वोट बैंक के रूप में देखने की राजनीति करती आई है। कांग्रेस शासन के दौरान 'खाम' की राजनीति गुजरात ने देखी है। 'खाम' की राजनीति का अर्थ है वर्ग-विशेष के लोगों को लामबंद कर वोट बैंक बनाकर चुनाव जीतना। इस बार भी कांग्रेस ने पाटीदार समाज में असंतोष फैलाकर हार्दिक पटेल के माध्यम से आंदोलन चलाने की कोशिश की। उसने अपनी ही पार्टी के एक हारे हुए जिला पंचायत सदस्य को 'ठाकोर सेना' नामक संगठन के रूप में खड़ा किया। जिग्नेश मेवाणी को 'दलित सेना' के नाम से खड़ा किया। यह साफ होता है कि राहुल गांधी ने जातिवादी ताकतों को आउटसोर्स किया। कांग्रेस सिर्फ भाजपा के प्रति एक भ्रम की स्थिति गुजरात के विभिन्न समाजों में फैलाना चाहती थी। इसके पीछे उसका मूल उद्देश्य यह था कि गुजरात आपस में बंट जाए और इसका राजनीतिक लाभ उसे मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस के जातिवाद के स्थान पर गुजरात के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सुशासन और विकास वाली राजनीति को ही वरीयता दी।

यह चुनाव 'लोकतंत्र' और 'वंशवाद' के बीच में भी था। इस चुनाव के दौरान ही 'वंशवादी राजनीति' की परंपरा को जारी रखते हुए राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने। वहीं, लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली भाजपा ने अपनी संगठनात्मक शक्ति को बढ़ाया। चुनाव शुरू होने से पहले ही भाजपा ने आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाई। पार्टी ने दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष की योजना के अंतर्गत विस्तारकों की

योजना का निर्माण किया जिसके द्वारा सभी बूथों तक विस्तारक गए। पार्टी ने मजबूत सांगठनिक ढांचे के माध्यम से शक्ति-केंद्र की स्थापना की, जिसके माध्यम से प्रत्येक राजनीतिक गतिविधि की निगरानी के साथ-साथ आम मतदाता से संपर्क रखने का कार्य हुआ। अपने विषयों और विचारों सहित 22 वर्षों का हिसाब राज्य की जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने घर-घर लोक संपर्क अभियान भी चलाया। एक तरफ जब कांग्रेस बैलगाड़ी की बात कर रही थी, तो भाजपा सी-प्लेन को प्रदेश की जनता के समक्ष विकास के एक मॉडल के रूप में लेकर आई। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट से दूर-देहात में स्थित ढेरों बांधों को जोड़ने का जो काम हुआ है, वह यह दर्शाता है कि अगर तकनीक अहमदाबाद के शहरी क्षेत्रों के लिए है तो ग्रामीण क्षेत्र के बांधों के लिए भी है। यह चुनाव 'न्यू इंडिया' बनाम 'मध्यकालीन युग' के बारे में भी था। यहां न्यू इंडिया का अर्थ है कि हम वे सभी निर्णय लें जो देशहित में हों। हम उन नीतियों को लागू करें और उन तकनीक का विकास करें जिससे देश आगे बढ़ सके। 'मध्यकालीन युग' का अर्थ है कि लोगों को जाति और कबीलों में बांटकर देखा जाए। यही कारण है कि राहुल गांधी से लेकर हार्दिक और जिग्नेश की सभा कभी भी किसी विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के बीच नहीं हुई। कुछ लोगों का हुजूम इकट्ठा करके उन लोगों ने यह माहौल बनाने की कोशिश की कि गुजरात में एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ है, जबकि वास्तविकता इसके उलट थी। कांग्रेस के विपरीत विभिन्न वर्गों और समूहों से बात करने के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का युवा टाउन हॉल कार्यक्रम हुआ जिसमें लाखों युवाओं ने भाग लिया, महिलाओं से संवाद के लिए सुषमा स्वराज का कार्यक्रम हुआ, दलित, ओबीसी, आदिवासी समाजों से सीधा संपर्क किया गया, प्रधानमंत्री ने भी कार्यकर्ताओं और विभिन्न वर्गों के साथ संवाद किया। ऐसे में समझा जा सकता है कि वैचारिक रूप से यह चुनाव 'न्यू इंडिया' बनाम 'मध्यकालीन युग' के बीच का था।

अगर इस चुनाव का समग्र विश्लेषण करें तो इस चुनाव में विकास के मुद्दे और सरकार के प्रति जनता का विश्वास स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि गुजरात में विकास की जो प्रक्रिया चली है उसका लाभ गुजरात के सभी लोगों को मिला है।

देश के लोकतंत्र में सुधारों का जो क्रम है, वह लंबे समय तक चलने वाला है। हमारे देश में सुशासन की राजनीति को लंबे समय तक जारी रखने की आवश्यकता है। गुजरात ने हाल के वर्षों में कृषि से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति की है उस दृष्टि से आवश्यक तकनीक, शासन में जनता की भागीदारी और समृद्धि सभी लोगों के पास हो। भारत जिन जीवन-मूल्यों को लेकर आगे बढ़ता रहा है, उनमें परिवार, संस्कृति, सौहार्द, विकास और तकनीक के नवीन प्रयोग द्वारा एक नए भारत के निर्माण का संकल्प है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य हैं)
(दैनिक जागरण से साभार)

रोजगार पैदा करने हेतु कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 20 दिसंबर को संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर कपड़ा क्षेत्र की समूची मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए एक नई कौशल विकास योजना को मंजूरी दी। इसे 'कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (एससीबीटीएस)' नाम दिया गया है। इस योजना को 1300 करोड़ रुपये के लागत-खर्च के साथ 2017-18 से लेकर 2019-20 तक की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है। इस योजना में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सामान्य मानकों के आधार पर राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होंगे।

योजना का उद्देश्य संगठित कपड़ा क्षेत्र और उससे जुड़े क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के संबंध में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित

करने के लिए मांग आधारित, प्लेसमेंट संबंधी कौशल कार्यक्रम, कपड़ा मंत्रालय के संबंधित संगठनों के माध्यम से कौशल विकास और कौशल उन्नयन को प्रोत्साहन देना तथा देश भर के हर वर्ग को आजीविका प्रदान करना है। ■

चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर को चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज में 2017-18 से लेकर 2019-20 तक के तीन वित्त वर्षों के दौरान 2600 करोड़ रुपये के स्वीकृत व्यय के साथ 'भारतीय फुटवियर, चमड़ा एवं सहायक सामान विकास कार्यक्रम' का कार्यान्वयन शामिल है।

प्रमुख लाभ

केन्द्रीय क्षेत्र की इस योजना से चमड़ा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, चमड़ा क्षेत्र से जुड़ी विशिष्ट पर्यावरणीय चिंताएं दूर होंगी, अतिरिक्त निवेश में सहूलियत होगी, रोजगार सृजन होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। ज्यादा कर प्रोत्साहन मिलने से इस क्षेत्र में व्यापक निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा और इस क्षेत्र के सीजनल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए श्रम कानून में सुधार से उत्पादन स्तर में वृद्धि संभव हो पाएगी।

विशेष पैकेज में तीन वर्षों के दौरान 3.24 लाख नये रोजगारों को सृजित करने की क्षमता है और इससे फुटवियर, चमड़ा एवं सहायक सामान क्षेत्र पर संचयी असर के रूप में दो लाख रोजगारों को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने में मदद मिलेगी।

भारतीय फुटवियर, चमड़ा एवं सहायक सामान विकास कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) उप-योजना : एचआरडी उप-योजना में 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से बेरोजगार व्यक्तियों को प्लेसमेंट से संबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण, 5000 रुपये प्रति कर्मचारी की दर से कार्यरत कामगारों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण और प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये की दर से प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का प्रस्ताव है। कौशल विकास प्रशिक्षण घटक से संबंधित सहायता प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत प्रशिक्षित व्यक्तियों का प्लेसमेंट अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इस उप-योजना के तहत 696 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय के साथ तीन वर्षों के दौरान 4.32 लाख बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने/कौशल प्रदान करने, 75000 मौजूदा कर्मचारियों का कौशल उन्नयन करने और 150 मुख्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है।

चमड़ा क्षेत्र के एकीकृत विकास (आईडीएलएस) की उप-योजना : आईडीएलएस उप-योजना के तहत मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण/तकनीकी उन्नयन के साथ-साथ नई इकाइयों की स्थापना के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को

नये संयंत्र एवं मशीनरी की लागत के 30 प्रतिशत की दर से और अन्य इकाइयों को संयत्र एवं मशीनरी की लागत के 20 प्रतिशत की दर से बैकएंड निवेश अनुदान/सब्सिडी प्रदान करके रोजगार सृजन सहित विनिर्माण एवं निवेश को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। इस उप-योजना के तहत 425 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय के साथ 3 वर्षों के दौरान चमड़ा, फुटवियर एवं सहायक सामान और कलपुर्जा क्षेत्र की 1000 इकाइयों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है।

संस्थागत सुविधाओं की स्थापना की उप-योजना : इस उप-योजना के तहत तीन वर्षों के दौरान 147 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय के साथ फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) के कुछ मौजूदा परिसरों का उन्नयन करके उन्हें 'उत्कृष्टता केंद्रों' में तब्दील करने और प्रस्तावित मेगा चमड़ा क्लस्टरों, जो परियोजना संबंधी प्रस्तावों पर आधारित होंगे, के आसपास पूर्ण सुविधाओं से युक्त तीन नये कौशल केंद्रों की स्थापना के लिए एफडीडीआई को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

मेगा चमड़ा, फुटवियर एवं सहायक सामान क्लस्टर (एमएलएफएसी) उप-योजना : एमएलएफएसी उप-योजना का उद्देश्य मेगा चमड़ा, फुटवियर एवं सहायक सामान क्लस्टर की स्थापना करके चमड़ा, फुटवियर एवं सहायक सामान क्षेत्र को बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान करना है। उपयुक्त परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक श्रेणीबद्ध सहायता देने का प्रस्ताव है, जिसमें भूमि की लागत शामिल नहीं होगी और इसके तहत अधिकतम सरकारी सहायता 125 करोड़ रुपये तक सीमित होगी। तीन वर्षों के दौरान 3-4 नये एमएलएफएसी को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए 360 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

चमड़ा प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ी उप-योजना : इस उप-योजना के तहत परियोजना लागत के 70 प्रतिशत

की दर से साझा अपशिष्ट शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) के उन्नयन/स्थापना के लिए सहायता देने का प्रस्ताव है। इस उप-योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर की क्षेत्रवार उद्योग परिषद/संघ को सहायता देने के साथ-साथ चमड़ा, फुटवियर एवं सहायक सामान क्षेत्र के लिए विजन दस्तावेज तैयार करने हेतु भी मदद दी जाएगी। इस उप-योजना हेतु तीन वर्षों के लिए प्रस्तावित परिव्यय 782 करोड़ रुपये है।

चमड़ा, फुटवियर एवं सहायक सामान क्षेत्र में भारतीय ब्रांडों को प्रोत्साहन देने की उप-योजना : इस उप-योजना के तहत ब्रांड के संवर्धन के लिए स्वीकृत पात्र इकाइयों को सहायता देने का प्रस्ताव है। इसके तहत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक साल सरकारी सहायता कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तय करना प्रस्तावित है, जो प्रत्येक ब्रांड के लिए अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। इस उप-योजना के तहत 90 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय के साथ 3 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 भारतीय ब्रांडों का संवर्धन करने का प्रस्ताव है।

चमड़ा, फुटवियर एवं सहायक सामान क्षेत्र के लिए अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन की उप-योजना: इस उप-योजना के तहत ईपीएफओ में नामांकन कराने वाले चमड़ा, फुटवियर एवं सहायक सामान क्षेत्र के सभी नये कर्मचारियों के लिए उनके नियोजन के प्रथम तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि में 3.67 प्रतिशत का नियोक्ता योगदान करने का प्रस्ताव है। यह उप-योजना 15000 रुपये तक का वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए मान्य होगी। 100 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय से संबंधित क्षेत्रों में लगभग 2,00,000 रोजगारों को औपचारिक करने में मदद मिलेगी।

विशेष पैकेज में श्रम कानूनों के सरलीकरण के लिए उपाय और रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन भी शामिल हैं, जिनका उल्लेख निम्न है:

आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेएए का दायरा बढ़ाना : किसी कारखाने में वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न भारतीय कंपनी द्वारा नये कर्मचारी को तीन वर्षों तक अदा किये गये अतिरिक्त पारिश्रमिक पर उसे टैक्स कटौती का लाभ देने हेतु आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेएए के तहत किसी कर्मचारी के लिए एक वर्ष में न्यूनतम 240 दिनों के रोजगार के प्रावधानों में और ज्यादा ढील देकर फुटवियर, चमड़ा एवं सहायक सामान क्षेत्र के लिए इसे न्यूनतम 150 दिन कर दिया जाएगा। यह कदम इस क्षेत्र के सीजनल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है।

निश्चित अवधि के रोजगार की शुरुआत : विश्व भर से व्यापक निवेश आकर्षित करने के लिए औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 15 की उप धारा (1) के तहत निश्चित अवधि वाले रोजगार की शुरुआत करके श्रम संबंधी मुद्दों के नियामकीय ढांचे को दुरुस्त करने का प्रस्ताव है। चमड़ा, फुटवियर एवं सहायक सामान उद्योग के मौसमी (सीजनल) स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। ■

स्वास्थ्य सुविधा में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और मोरक्को ने सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

स्वास्थ्य सुविधा में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और मोरक्को ने 14 दिसंबर को सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। सहमति-ज्ञापन पर भारत की तरफ से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी.नड्डा और मोरक्को के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. अब्दुलकादिर अमारा ने हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारियों सहित मोरक्को का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल उपस्थित था।

श्री जे.पी.नड्डा ने कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत और समृद्ध पारंपरिक रिश्ते हैं। उन्होंने भारत की बेहतरीन जेनेरिक दवाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत इन दवाओं का 200 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है और हमारे यहां एक मजबूत जन स्वास्थ्य प्रणाली काम करती है। इस प्रणाली की निगरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिये की जाती है। श्री नड्डा

ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहमति-ज्ञापन के दायरे में दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाने में सक्षम होंगे और स्वास्थ्य क्षेत्र में एक-दूसरे का सहयोग करेंगे।

दोनों देशों के बीच सहयोग के मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- बाल हृदय रोग और कैंसर सहित गैर-संचारी रोग
- औषधि नियमन एवं गुणवत्ता नियंत्रण
- संचारी रोग
- मातृत्व, बाल एवं पूर्व-प्रसव स्वास्थ्य
- बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के आदान-प्रदान के लिए अस्पतालों के बीच सहयोग
- स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों के प्रबंधन और प्रशासन में प्रशिक्षण

एक दूसरा सहमति-ज्ञापन जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और और मराकेश मोहम्मद विश्व विद्यालय अस्पताल के बीच हुआ। इस अवसर पर दोनों देशों के मंत्री मौजूद थे। दोनों देशों के संस्थानों ने टेली-मेडिसन के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति व्यक्त की। ■

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय: वर्षान्त समीक्षा-2017

स्वच्छ भारत मिशन

सार्वभौमिक स्वच्छता क्षेत्र को प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और सुरक्षित स्वच्छता की पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) का शुभारंभ किया। एसबीएम का उद्देश्य 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) राष्ट्र और स्वच्छ भारत बनाना है, जिससे उनकी 150वीं जयंती पर उपयुक्त श्रद्धांजलि दी जाए।

ओडीएफ परिणामों की उपलब्धि के लिए व्यवहार परिवर्तन पर प्राथमिक ध्यान देना एक मौलिक साधन है। मंत्रालय इसे अपने केंद्रित सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आईईसी) कार्यक्रमों के द्वारा कार्यान्वित कर रहा है। यह लैंगिक संवेदनशील सूचना, व्यवहार परिवर्तन दिशानिर्देश और विभिन्न जन शिक्षा गतिविधियों को प्रोत्साहन देता है। मंत्रालय ने 2017 में लैंगिक दिशानिर्देश और 2015 में मासिक धर्म प्रबंधन दिशानिर्देशों को जारी किया।

स्वच्छ भारत मिशन: स्वच्छता को हर किसी का कार्यक्षेत्र बनाना

एमडीडब्ल्यूएस में एसबीएम-ग्रामीण के आवंटित प्रभार के अलावा स्वच्छ भारत की उपलब्धि की दिशा में सभी गतिविधियों और पहलों का आयोजन और समन्वय करना अनिवार्य है। इस दायित्व को पूर्ण करने के लिए, मंत्रालय निरंतर अन्य सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, विश्वास संगठनों, मीडिया और हितधारकों के साथ कार्य करता है। यह दृष्टिकोण प्रधानमंत्री के आह्वान पर आधारित है कि स्वच्छता केवल विभागों की ही नहीं, हर किसी का कार्य हो। विशेष पहलों और परियोजनाओं की मेजबानी को इस प्रक्रिया में त्वरित समय से किया जाना चाहिए। सभी हितधारकों की प्रतिक्रिया बेहद उत्साहजनक रही है।

स्वच्छता पखवाड़ा

केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को उनके अधिकार क्षेत्र में शामिल करते हुए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ अप्रैल 2016 में स्वच्छता के मुद्दों और कार्यप्रणालियों पर गहन ध्यान केंद्रित करने के एक पखवाड़े के उद्देश्य से किया गया था। पखवाड़ा गतिविधियों के लिए योजना में सहायता के लिए मंत्रालयों के बीच एक वार्षिक कैलेंडर का पूर्व वितरण किया जाता है।

नमामि गंगे

नमामि गंगे कार्यक्रम जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) की एक पहल है जिसके अंतर्गत गंगा नदी के किनारों पर बसे गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाना और एमडीडब्ल्यू के द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 52 जिलों में स्थित सभी 4470 गांवों को राज्य सरकारों की सक्रिय मदद से खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब मंत्रालय ने एनएमसीजी के सहयोग से गंगा नदी के किनारे के 24 गांवों को गंगा ग्राम में बदलने का दायित्व लिया है।

स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)

स्वच्छता के लिए अपनी तरह के प्रथम अंतर-मंत्रालयी कार्यक्रम एसएपी, प्रधानमंत्री के परिकल्पना का एक दृढ़ साकार रूप है कि स्वच्छता हर किसी का कार्य है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने उचित बजट प्रावधानों के साथ महत्वपूर्ण तरीके से इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से बजट विभागाध्यक्ष बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 77 मंत्रालयों/विभागों ने अपने एसएपी के लिए 12468.62 करोड़ रुपये की धनराशि के उपयोग की वचनबद्धता की है। एसएपी कार्यांवयन 1 अप्रैल 2017 से प्रारंभ कर दिया गया है।

स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल (एसआईपी)

माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा के अंतर्गत, मंत्रालय ने संपूर्ण भारत में ऐसे 100 स्थलों की स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहु-हितधारक पहल की है जो अपनी विरासत, धार्मिक और सांस्कृतिक

महत्व के कारण "प्रतिष्ठित" हैं।

इस पहल का लक्ष्य इन स्थलों में स्वच्छता की स्थिति में एक उच्चतर स्तर तक सुधार किया जाए। इस पहल में शहरी विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के साथ एमडीडब्ल्यूएस एक नोडल मंत्रालय के रूप में साझेदारी में है। अब तक पहले दो चरणों में 20 प्रतिष्ठित स्थलों पर कार्यवाही को अंजाम दिया जा चुका है। इन सभी 20 प्रतिष्ठित स्थलों को वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए पीएसयू या कॉरपोरेट्स के तौर पर नामित किया गया है।

स्वच्छ शक्ति, 8 मार्च, 2017

स्वच्छ शक्ति का आयोजन 8 मार्च, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गांधीनगर के महात्मा मंदिर मे किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जन सभा को भी संबोधित किया। देश भर से लगभग 6,000 चयनित महिला सरपंचों, निचले स्तर के कामगारों ने इस समारोह में भाग लिया और ग्रामीण भारत में स्वच्छ भारत को एक वास्तविकता बनाने की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वच्छता चैंपियंस को सम्मानित किया गया।

खुले में शौच से मुक्ति (एफओडी) सप्ताह (अगस्त 9– अगस्त 15)

ग्रामीण क्षेत्रों के सभी समुदायों में जागरूकता सृजन और जन फैलाव के माध्यम से भीतरी व्यवहार परिवर्तन हेतु घर से घर तक, स्वच्छता रथों, रैलियों, मैराथनों, चैंपियंनों को प्रोत्साहन, प्रश्नोत्तरी/चित्रकारी प्रतिस्पर्धाओं जैसी आईईसी गतिविधियों का आयोजन किया गया।

स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि प्रतियोगिता (17 अगस्त –8 सितम्बर)

माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प से स्वच्छ सिद्धि के अंतर्गत 2022 तक एक नया भारत बनाने का आह्वान किया, ताकि सामूहिक रूप से सभी को भारत से गंदगी के समाप्त करने के लिए एक संकल्प दिलाया जा सके। इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने की दिशा में, पेयजल और

स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में 17 अगस्त से 8 सितंबर 2017 के बीच एक देशव्यापी फिल्म, निबंध और चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया।

स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस), सितम्बर 16– अक्टूबर 2, 2017

27 अगस्त, 2017 को अपने मन की बात कार्यक्रम के संबोधन में, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से स्वच्छता की भावना का आह्वान करते हुए 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर, 2017 के दौरान स्वच्छता गतिविधियों में तेजी लाने हेतु सभी गैर सरकारी संगठनों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नेताओं, कॉरपोरेटों, सरकारी

नमामि गंगे कार्यक्रम जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) की एक पहल है, जिसके अंतर्गत गंगा नदी के किनारों पर बसे गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाना और एमडीडब्ल्यू के द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

अधिकारियों, कलेक्टरों और सरपंचों से श्रमदान गतिविधियों को कार्यान्वित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के शहंशाहपुर गांव में दो गड्ढे वाले शौचालय के निर्माण में श्रमदान के अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि 'स्वच्छता को 'स्वभाव' बनाना है- और हमें अपने राष्ट्र को स्वच्छ बनाने के लिए यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है' । एसएचएस को एक व्यापक प्रतिक्रिया मिली और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के प्रति श्रमदान हेतु स्वेच्छा से सेवा के लिए देशभर में सशस्त्र बलों और दिव्यांगों सहित नागरिकों ने बड़े पैमाने पर इसमें सामूहिक भागीदारी को अंजाम दिया है।

दरवाजा बंद मीडिया अभियान

व्यवहार परिवर्तन के लक्ष्य को लेकर, विशेष रूप से पुरुषों के द्वारा शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के अमिताभ बच्चन के साथ 'दरवाजा बंद' नामक शीर्षक से एक प्रगतिशील जन मीडिया अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान में हिंदी और 9 भाषाओं सहित 5 टीवी और रेडियो स्पॉट शामिल हैं और इसे देश भर के जन मीडिया पर सफलतापूर्वक प्रारंभ किया जा चुका है। ■

प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान 'ओखी' से प्रभावित लोगों से मुलाकात की

तत्काल 325 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 दिसंबर को लक्षद्वीप, तमिलनाडु और केरल के चक्रवाती तूफान 'ओखी' से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और तूफान से प्रभावित लोगों, मछुआरों तथा किसानों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कावारत्ती और कन्याकुमारी में लोगों से बातचीत की। उन्होंने तिरुअनंतपुरम के निकट अवस्थित पुन्थुरा गांव का भी दौरा किया, जो इस चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित गांवों में से एक है। तूफान से हुई परेशानियों को लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। प्रधानमंत्री ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी क्षमता के साथ इस प्रतिकूल हालात में राज्य के साथ खड़ी है।

प्रधानमंत्री ने कावारत्ती, कन्याकुमारी और तिरूअनंतपुरम में वर्तमान स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा के लिए अलग-अलग बैठकें की। केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष और लक्षद्वीप के प्रशासक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षा बैठकों में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार चक्रवाती तूफान प्रभावित राज्यों की हरसंभव मदद करेगा।

केंद्र सरकार केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के लिए तत्काल 325 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद जारी करेगा। प्रधानमंत्री द्वारा आज घोषित की गई आर्थिक मदद, इस महीने की शुरुआत में तमिलनाडु को 280 करोड़ रुपये और केरल को दी गई 76 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद से अलग है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ओखी तूफान के कारण ध्वस्त हुए करीब 1400 मकानों के पुनर्निर्माण में मदद करेगी। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को नये घर के निर्माण के लिए

डेढ़ लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। बीमा कंपनियों को ओखी तूफान पीड़ितों के दावों को शीघ्रता से निपटाने की सलाह दी गई है। तूफान के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से देने की मंजूरी दी गई है।

इससे पहले समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री को चक्रवाती तूफान ओखी के असर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस क्षेत्र में पिछले 125 वर्षों में इस तरह का यह तीसरा तूफान था। यह चक्रवाती तूफान 30 नवंबर, 2017 को आया और उसी दिन तलाश एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने कुल 845 मछुआरों को सफलतापूर्वक बचाया। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि तट से 700 समुद्री मील से भी अधिक दूरी तक निगरानी की गई। ■

नवबंर,2017 तक प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

वित्तीय वर्ष 2017-18 में नवबंर, 2017 तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण (अंनतिम) 4.8 लाख करोड़ रुपये रहा और इसमें गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहण, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रत्यक्ष कर के कुल बजट अनुमान 9.8 लाख करोड़ रुपये के 49 प्रतिशत को दर्शाता है। अप्रैल-नवबंर,2017 की अवधि में सकल संग्रहण (धन वापसी समायोजन से पहले) 5.82 लाख करोड़ रुपये रहा और इसमे 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल,2017 से नवंबर 2017 तक 1.02 लाख करोड़ रुपये की धन वापसी की गई। ■

उद्योग संघों को देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 दिसंबर को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की 90वीं वार्षिक आम बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। 1927 में फिक्की के स्थापना समय को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय उद्योग ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित साइमन कमीशन के खिलाफ एकजुट हुआ था। उन्होंने कहा कि उस समय भारतीय उद्योग समाज के हर वर्ग के साथ खड़ा था।

श्री मोदी ने कहा कि आज भी वैसा ही माहौल मौजूद है, जब देशवासी राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि देश को भ्रष्टाचार और कालेधन जैसी घरेलू समस्याओं से निजात मिले। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और उद्योग संघों को देश की जरूरतों तथा लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन कई चुनौतियां भी खड़ी हो गयी हैं। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा और बैंक खातों, गैस कंनेक्शनों, छात्रवृत्तियों, पेंशन इत्यादि जैसे मुद्दों पर जूझना पड़ता रहा। केन्द्र सरकार इस संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। उसका प्रयास है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाये जो पारदर्शी और संवेदनशील हो। उन्होंने कहा कि जनधन योजना इसकी एक मिसाल है और 'जीवन की सहजता' बढ़ाने पर केन्द्र सरकार ध्यान दे रही है।

उन्होंने उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद गरीबी देखी है और वे इस बात को बखूबी समझते हैं कि गरीबों और राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता है। उन्होंने उद्यमियों को गैर-जमानती ऋण प्रदान करने वाली मुद्रा योजना का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि फंसे कर्ज (एनपीए) की समस्या वर्तमान सरकार को विरासत में मिली है। उन्होंने कहा कि अब वित्तीय नियमन एवं जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खाताधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए काम कर रही है, लेकिन इसके विपरीत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि फिक्की जैसे संगठनों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऐसे मुद्दों पर लोगों में जागरूकता पैदा करें। उन्होंने कहा कि इसी तरह फिक्की को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को और कारगर

बनाने के लिए भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक व्यापार गतिविधियों का जीएसटी के लिए पंजीकरण सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि व्यवस्था जितनी औपचारिक बनेगी, गरीबों को उतना अधिक फायदा होगा। इससे बैंकों से आसानी से ऋण मिलेगा, लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आएगी, जिसके कारण व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि छोटे कारोबारियों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने के लिए फिक्की के पास जरूर कोई योजना होगी। उन्होंने यह भी कहा कि फिक्की को जरूरत आने पर बिल्डरों द्वारा आम आदमी के शोषण जैसे मुद्दों के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने यूरिया, कपड़ा, नागरिक विमानन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के लिए नीतिगत फैसलों तथा उनके लाभों का भी उल्लेख किया। उन्होंने रक्षा, निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण जैसे अन्यान्य क्षेत्रों में होने वाले सुधारों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उपरोक्त उपायों के नतीजे में विश्व बैंक की 'व्यापार करने की आसानी' रैंकिंग में भारत 142वें स्थान से उठकर 100वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने उन संकेतकों का भी हवाला दिया, जो भारत की सेहतमंद अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उठाये गये कदम रोजगार पैदा करने की दिशा में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण, स्टार्टअप, मशीनों से प्राप्त होने वाली जानकारी, सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में फिक्की की मुख्य भूमिका है। उन्होंने फिक्की से आग्रह किया कि वह एमएसएमई क्षेत्र के लिए थिंक-टैंक की भूमिका निभाये। ■

कौशल उन्नयन के लिए 2,327 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

युवा मामले विभाग (युवा मामले व खेल मंत्रालय) के नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) ने 2017 के दौरान कौशल उन्नयन के लिए 2,327 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये, जिसमें 69,597 युवको व युवतियों ने भाग लिया। दरअसल, 1.42 लाख युवा क्लबों में नामांकित 3.15 लाख युवा सदस्यों की सहायता से एनवाईकेएस युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए कार्यरत है। एनवाईकेएस की कुछ महत्वपूर्ण पहलें / उपलब्धियां निम्न हैं:

- एनवाईकेएस कार्यकर्ताओं द्वारा 7.93 लाख पौधों को लगाया गया।
- एनवाईकेएस कार्यकर्ताओं द्वारा 10166 यूनिट रक्तदान किया गया।
- युवा नेतृत्व तथा सामुदायिक विकास के लिए 280 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें 12,301 युवाओं ने हिस्सा लिया।
- युवा क्लब विकास के लिए 1854 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 1,55,873 युवाओं ने भाग लिया।
- ब्लॉक और जिला स्तर पर 1331 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें 167605 युवाओं ने हिस्सा लिया।
- राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व के दिवस समारोहों के लिए 8054 कार्यक्रम आयोजित किये गये। इसमें 11,19,587 युवाओं ने भाग लिया।
- 240 जिला युवा सम्मेलन आयोजित किये गये। इसमें 1,36,734 युवाओं ने भाग लिया।
- 1,04,279 स्थलों पर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें 8,72,813 युवाओं ने 8,825 स्कूलों / कॉलेजों, 7,720 अस्पतालों तथा 19,437 प्रतिमाओं की साफ सफाई की। कुल 9,29,737 कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसमें 59,74,990 युवाओं ने भाग लिया।
- जल संरक्षण के लिए 13,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये। इसमें 3.8 लाख युवाओं ने भाग लिया। 2,260 छोटे जलाशयों का निर्माण किया गया तथा 3,139 जल स्रोतों को सुव्यवस्थित किया गया।
- इन्द्रधनुष कार्यक्रम के तहत 52,317 बच्चों को रोग प्रतिरोधक दवा पिलाई गई।
- जिला नेहरू युवा केन्द्रों ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किये। इसमें 2.5 लाख युवाओं ने भाग लिया।
- जिला नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा संपूर्ण भारत में संविधान दिवस तथा कौमी एकता दिवस के तहत कार्यक्रम आयोजित किये गये।

जल संरक्षण के लिए 13,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये। इसमें 3.8 लाख युवाओं ने भाग लिया। 2,260 छोटे जलाशयों का निर्माण किया गया तथा 3,139 जल स्रोतों को सुव्यवस्थित किया गया।

दिल्ली स्लम आंदोलन – दिल्ली के स्लमों में सामाजिक निर्माण और विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किये गये। इसके तहत 12 स्लम युवा दौड और बैठकें आयोजित की गईं। स्लम के युवाओं ने इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस – एनवाईकेएस ने 14 राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए, इसमें 34,007 युवाओं ने भाग लिया। 384 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किये गये। इसमें 2,55,474 युवाओं ने भाग लिया। गांव स्तर पर 37,286 युवा क्लबों ने योग प्रदर्शन आयोजित किये। इसमें 10,44,518 युवाओं ने हिस्सा लिया।

स्वच्छता पखवाड़ा - एनवाईकेएस ने 1 से 15 अगस्त 2017 तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सभी स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित किये। गांवों की सफाई के लिए 104279 युवा क्लबों ने स्वच्छता

अभियान चलाया, इसमें 8,72,813 युवाओं ने भाग लिया। 1,95,545 युवाओं की भागीदारी से 8237 रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, बाजारों व ऐतिहासिक स्थलों की साफ सफाई की गई। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत 9,29,737 कार्यक्रम आयोजित किये गये। इसमें 59,74,990 युवाओं ने भाग लिया।

स्वच्छता ही सेवा अभियान – एनवाईकेएस ने युवा कार्यकर्ताओं, क्लबों व स्थानीय युवाओं की सहायता से लोगों को अपने आसपास की स्वच्छता के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये। 20,384 युवा क्लबों में गावों में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किये। कुल 38,495 कार्यक्रम आयोजित किये गये। इसमें 2,05,154 युवाओं ने भाग लिया।

स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि – स्वच्छ भारत मिशन में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निबंध लेखन, लघु फिल्म निर्माण प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किये गये। विजेताओं को नकद पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र दिया गया।

विशेष कार्यक्रम

- चम्पारन सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने के अवसर पर बिहार सरकार की सहायता से मोतिहारी में 15 से 19 अप्रैल 2017 तक कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनवाईकेएस के 768 युवाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
- एनवाईकेएस ने गुवाहाटी में 23 मई 2017 को युवा सम्मेलन आयोजित किया।
- एनवाईकेएस ने रायपुर में 25 मई 2017 को युवा सम्मेलन आयोजित किया।
- एनवाईकेएस ने कोझीकोड में 15 जून 2017 को युवा सम्मेलन आयोजित किया।
- एनवाईकेएस ने गंगटोक में 04 जून 2017 को युवा सम्मेलन आयोजित किया।
- नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत एनवाईकेएस ने गंगा किनारे स्थित गांवों में स्वच्छता के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।
- गंगा निरीक्षण यात्रा - (26 मई से 9 जून 2017)
- गंगा दशहरा समारोह - (3 और 4 जून 2017) एनवाईकेएस ने 4 राज्यों - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के 53 ब्लॉकों में समारोह आयोजित किये।
- गंगा वृक्षारोपण शपथ – 25 जुलाई से 31 जुलाई 2017
- एनवाईकेएस ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 30 जिलों के गंगा तट पर 1,12,246 पौधे लगाए।

पर्यटन पर्व - एनवाईकेएस ने 5 से 25 अक्टूबर 2017 तक पर्यटन के महत्व से लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किये। वित्त मंत्री ने युवा व खेल मंत्रालय तथा एनवाईकेएस को पुरस्कृत किया।

आदिवासी युवा कार्यक्रम – एनवाईकेएस ने 7 राज्यों (छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार) के 10 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किये।

पूर्वोत्तर युवा कार्यक्रम – एनवाईकेएस ने 4 स्थानों (हिसार, तिरूअनंतपुरम, जम्मू व पुणे) पर कार्यक्रम आयोजित किये। इसमें 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 1 हजार युवाओं ने भाग लिया।

एक भारत श्रेष्ठ भारत – एनवाईकेएस ने अंतरराज्यीय युवा आदान – प्रदान कार्यक्रम के तहत 15 राज्यों की सहभागिता से कार्यक्रम आयोजित किए। ■

सरकारी संस्थानों पर होने वाले साइबर हमलों से रक्षा करेगा सीईआरटी

विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने श्री रविशंकर प्रसाद ने 11 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के तहत "एनआईसी-सीईआरटी" का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान श्री प्रसाद ने कहा कि डिजिटल भारत पहल के तहत सरकार ने अपनी कई सेवाओं को ऑनलाइन किया है। उन्होंने कहा कि भले ही ऑनलाइन प्रणाली से कई सरकारी सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच सुगम हुई हो, लेकिन लोगों को साइबरस्पेस से जुड़े खतरों के प्रति भी सजग करना होगा।

श्री प्रसाद ने कहा कि हाल ही में साइबर हमलों में तेजी आई है, जिससे डाटा चोरी होने की चिंताएं बढ़ गईं हैं। इससे निपटने के लिए सरकार डाटा संरक्षण अधिनियम का मसौदा तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट बेहद तेजी से बढ़ रहा है और यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शामिल है। इसलिए मौजूदा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एनआईसी के उल्लेखनीय काम-काज की सराहना करते हुए कहा कि एनआईसी लंबे समय से सरकारी साइबरस्पेस की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। इस केंद्र की स्थापना से एनआईसी ने अपने अनुभव और विशेषज्ञता के स्तर को और ऊंचा किया है। ■

मिशन इन्द्रधनुष के तहत 2.5 करोड़ बच्चे लाभान्वित: जे.पी. नड्डा

हम देश में यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमने विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने 11 दिसंबर को यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 2017 मनाने के उद्देश्य से आयोजित एक समारोह में ये बातें कहीं। वित्त राज्य मंत्री श्री एस.पी. शुक्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री और वित्त राज्य मंत्री ने 'लक्ष्य' - प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल के साथ-साथ परिधीय क्षेत्रों में शिशुओं के सामान्य एवं जटिल प्रसव का प्रबंधन करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए सुरक्षित प्रसव मोबाइल एप का भी शुभारंभ किया और इसके साथ ही प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयों (एचडीयू) एवं गहन देखभाल इकाइयों (आईसीयू) के लिए परिचालन दिशा-निर्देश भी जारी किये।

श्री नड्डा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह वर्ष विशेष अहमियत रखता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को मंजूरी दी गई है, जिसमें किसी वित्तीय कठिनाई के बगैर ही स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मरीजों द्वारा अपनी जेब से किये जाने वाले अतिरिक्त व्यय (ओओपीई) में कमी के लिए ठोस कदम उठाए हैं। वर्ष 2014 में मिशन इन्द्रधनुष का शुभारंभ किया गया था, जिसे सबसे बड़ी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में शुमार किया जाता है। अब तक मिशन इन्द्रधनुष के चार चरण पूरे हो चुके हैं और इस दौरान 528 से भी अधिक जिलों में 2.5 करोड़ बच्चों तक इसकी सफल पहुंच हो चुकी है। श्री नड्डा ने बताया कि हम टीकों की संख्या में बढ़ोतरी करने पर भी अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। हमने रोटावायरस टीका, न्यूमोकोकल संयुग्म वैक्सीन (पीसीवी) और खसरा-रूबेला (एमआर) वैक्सीन के साथ-साथ वयस्कों के लिए जेई टीका भी लांच किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री डायलिसिस कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत 1.43 लाख मरीजों ने 1,069 डायलिसिस इकाइयों से निःशुल्क सेवाएं प्राप्त की हैं। इसके अलावा निःशुल्क दवा एवं निदान कार्यक्रम से भी ये मरीज लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह लगभग 47 लाख मरीज रियायती दवाओं की खरीद के जरिए अमृत फार्मेसी से लाभान्वित हुए हैं।

श्री नड्डा ने उपस्थित लोगों को यह भी जानकारी दी कि व्यापक प्राथमिक देखभाल सुलभ कराने के लिए सरकार ने 1.5 लाख उप-सेवा केन्द्रों को स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्रों में तब्दील करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय अब स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के जरिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान करने की दिशा में अग्रसर है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए वित्त राज्य मंत्री श्री एस.पी शुक्ला ने कहा कि सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक संसाधन सुलभ कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट में 27.7 प्रतिशत की वृद्धि की है।

लक्ष्य– प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल

इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि विशेषकर शिशुओं के जन्म के समय प्रसव कक्षों में देखभाल की गुणवत्ता बेहतर करना अत्यंत जरूरी है, ताकि मां एवं नवजात शिशु दोनों के ही जीवन को कोई खतरा न हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार 'लक्ष्य- प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल' का शुभारंभ कर रही है। 'लक्ष्य' से प्रसव कक्षों और ऑपरेशन थियेटर में गर्भवती मां की देखभाल बेहतर होने की उम्मीद है। इससे नवजात शिशुओं के जन्म के समय अवांछनीय प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने से बचा जा सकेगा। यह पहल सरकारी मेडिकल कॉलजों के अलावा जिला अस्पतालों (डीएच), ज्यादा डिलीवरी लोड वाले उप-जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी अमल में लाई जाएगी।

प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयों (एचडीयू) एवं गहन देखभाल इकाइयों (आईसीयू) के लिए परिचालन दिशा–निर्देश

नवजात शिशु के जन्म के समय मां की मृत्यु की संभावनाएं कम करने के लिए जटिल मामलों में अत्यधिक देखभाल सुनिश्चित करना अत्यंत जरूरी है। इसके लिए भारत सरकार ने वर्ष 2016 में प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयों (एचडीयू) एवं गहन देखभाल इकाइयों (आईसीयू) की स्थापना हेतु परिचालन दिशा-निर्देश जारी किये थे। इन दिशा-निर्देशों के तहत प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयों (एचडीयू) एवं गहन देखभाल इकाइयों (आईसीयू) की एक व्यापक अवधारणा पेश की गई थी। अब हम प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयों (एचडीयू) एवं गहन देखभाल इकाइयों (आईसीयू) के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं। ये दिशा-निर्देश दरअसल मौजूदा राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के पूरक साबित होंगे और इनसे राज्यों एवं राज्य स्तरीय नीति निर्माताओं को मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों में उन गहन देखभाल इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन करने में मदद मिलेगी, जो गर्भवती महिलाओं और हाल ही में नवजात शिशुओं को जन्म देने वाली माताओं को समर्पित होंगी।

सुरक्षित प्रसव एप

सुरक्षित प्रसव एप एक मोबाइल हेल्थ टूल है, जिसका उपयोग परिधीय क्षेत्रों में शिशुओं के सामान्य एवं जटिल प्रसव का प्रबंधन करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए किया जा सकता है। इस एप में महत्वपूर्ण प्रसूति प्रक्रियाओं पर नैदानिक निर्देशात्मक फिल्में डाली गई हैं, जिनसे स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपने कौशल को व्यवहार में लाने में मदद मिलेगी। यह एप प्रशिक्षण देने, प्रदर्शन इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस एप को भारतीय संदर्भ के अनुसार तैयार किया गया है। कुछ जिलों में इसका फील्ड परीक्षण किया जा चुका है और इसे विशेषकर उन स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए काफी उपयोगी पाया गया है, जो मातृत्व देखभाल से जुड़े हुए हैं। ■

भारत और मोरक्को ने जल संसाधन, सड़क और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किये

मोरक्को सरकार के एक शिष्टमंडल ने वहां के उपकरण, यातायात, लॉजिस्टिक्स और जल मंत्री श्री अब्दुलकादिर अमारा के नेतृत्व में सड़क यातायात एवं राजमार्ग, नौवहन और जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी से 14 दिसंबर को मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सड़क यातायात, जल संसाधन और समुद्री क्षेत्र में भारत-मोरक्को द्विपक्षीय सहयोग संबंधी विषयों पर चर्चा की। दोनों देशों ने निम्नलिखित सहमति-ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर कियेः

- जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति-ज्ञापन।
- भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय और मोरक्को के हायर इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज के बीच सहयोग के लिए समझौता।

- मोरक्को के नेशनल पोर्ट्स एजेंसी और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के बीच प्रशिक्षण में सहयोग के लिए समझौता।
- मोरक्को के इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग इन इंजन्स एंड रोड मेन्टिनेंस तथा भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी (आईएएचई) के बीच समझौता।

इस अवसर पर श्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच सड़क यातायात, जल संसाधन और समुद्री क्षेत्रों में बड़े सहयोग की उम्मीद करते हैं। ■

परिवहन से परिवर्तन लाना हमारा मकसद: नरेंद्र मोदी

गत 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मेघालय और मिजोरम के प्रवास पर थे। उन्होंने आइजोल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट और शिलॉन्ग में तुरा रोड प्रोजेक्ट का उदघाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पावर प्लान्ट मिजोरम में केंद्र सरकार का पहला कामयाब प्रोजेक्ट है। वाजपेयी जी ने नॉर्थ-ईस्ट के विकास की शुरुआत की थी। सरकार की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' से नॉर्थ-ईस्ट, दक्षिण-पूर्व एशिया का गेटवे बनेगा। पड़ोसी देशों के साथ कारोबार के नए रास्ते खुलेंगे। हमने यहां रोड, रेल और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए करीब 180 हजार करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है। सीप्लेन के इस्तेमाल से यहां भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

शिलॉन्ग में श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ''नए रोड प्रोजेक्ट से मेघालय में शिलॉन्ग और तुरा के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सफर में वक्त घटेगा। हमारा लक्ष्य साफ है कि ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसफार्मेशन। 2014 में हमारी सरकार आई तो मैंने साफ निर्देश दिए कि कोई न कोई मंत्री हर 15 दिन में नॉर्थ-ईस्ट का दौरा करे। यह दौरा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सुबह आए और शाम को वापस दिल्ली आ जाओ। वे यहां आकर रुकते हैं और आप लोगों से मुलाकात करते हैं।''

श्री मोदी ने कहा, ''पूरे नॉर्थ-ईस्ट में 4 हजार किलोमीटर लंबे रोड और हाइवे बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 32 हजार करोड़ रुपए के फंड मंजूर किया है। सरकार यहां 14 हजार किलोमीटर लंबी 15 नई रेल लाइन बिछा रही है। इसकी लागत 47 हजार करोड़ है।''

उन्होंने कहा, ''मोरारजी देसाई के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री नॉर्थ-ईस्टर्न काउंसिल में शामिल हुआ तो वह मैं था। पिछले साल मैंने शिलॉन्ग में इस काउंसिल की मीटिंग का उद्घाटन किया था।''

उन्होंने कहा, ''पिछले साल मेघालय के दौरे पर मैंने यहां टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की अपील की थी। हम इस राज्य को टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ का फंड मंजूर किया है।''

उन्होंने कहा, ''2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे होंगे। इसी दौरान मेघालय की स्थापना के भी 50 साल पूरे हो जाएंगे। यह राज्य के लिए नया संकल्प लेने के लिए बड़ा अवसर होगा।''

श्री नरेंद्र मोदी ने आइजोल में कहा, ''हाइड्रो पावर प्लान्ट मिजोरम में केंद्र सरकार का पहला कामयाब प्रोजेक्ट है। वाजपेयी जी ने नॉर्थ-ईस्ट में विकास की शुरुआत की थी। उनके कार्यकाल में शुरू हुई विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार के मंत्री समय-समय पर नॉर्थ-ईस्ट का दौरा करते रहे हैं।''

उन्होंने कहा, ''यह प्रोजेक्ट 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पास हुआ था, लेकिन इसके बाद इसमें देरी हुई। हाइड्रो प्रोजेक्ट नॉर्थ-ईस्ट के विकास में अहम रोल निभाएगा।''

उन्होंने कहा, ''इस खूबसूरत राज्य में आकर यहां के लोगों के

साथ बिताए पलों की यादें ताजा हो गईं। मैं सभी लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं।''

MyDoNER App लॉन्च करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ''नॉर्थ-ईस्ट का ध्यान रखते हुए सरकार ने DONER (Ministry for Development of North Eastern Region) मंत्रालय बनाया है, जिसने 100 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया है। इसके लिए आपको दिल्ली सरकार का शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं।''

उन्होंने कहा, ''मेरा मिजोरम के नौजवानों से आग्रह है कि वो केंद्र सरकार की इन योजनाओं का फायदा उठाएं। यहां के नौजवान स्टार्टअप की दुनिया में छा जाने का हौसला रखते हैं। भारत सरकार ऐसे नौजवानों की हैंड होल्डिंग के लिए हमेशा तैयार है। फुटबॉल दुनिया में मिजोरम की पहचान बन सकता है।''

श्री मोदी ने कहा, ''केंद्र सरकार 2022 तक न्यू इंडिया बनाना चाहती है, इसके लिए सरकार कई तरह के डेवलेपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत सरकार नॉर्थ-ईस्ट में हाईवे और रोड का नेटवर्क बना रही है।''

उन्होंने कहा, ''दिल्ली सरकार काफी सक्रियता के साथ 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को लेकर काम कर रही है। इसे साउथ-ईस्ट एशिया के गेटवे के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं। मिजोरम को इससे काफी फायदा मिलेगा। पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश के साथ कारोबार का नया रास्ता खुलेगा।''

दौरे से पहले श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा- ''हम देखते हैं कि नॉर्थ-ईस्ट में बहुत क्षमता है। इस क्षेत्र के बेहतर विकास के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। मुझे नॉर्थ-ईस्ट से बुलावा आया है। मिजोरम और मेघालय जाने के लिए बेताब हूं। यहां कई अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत से विकास को गति मिलेगी।'' ■

जनादेश के निहितार्थ

भारतीय जनता पार्टी अपना गुजरात का किला बचाने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस के हाथ से उसने हिमाचल प्रदेश को छीन लिया। गुजरात में भाजपा पिछले 22 साल से सत्ता में है और अब राज्य के मतदाताओं ने एक और कार्यकाल के लिए उसे जनादेश दिया है। जबकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ पांच साल के कार्यकाल के बाद कांग्रेस के खिलाफ ऐसा माहौल बना कि मतदाताओं ने 68 सदस्यों वाली विधानसभा में उसे महज 21 सीटों पर समेट दिया। वहां 44 सीटें जीतकर भाजपा ने बड़ी विजय प्राप्त की है।

गुजरात में भाजपा के सामने कई मुश्किल चुनौतियां थीं। गुजरे तीन वर्षों में वहां के पाटीदार और दलित समुदाय आंदोलन पर उतरे। पाटीदारों के आरक्षण की मांग के जवाब में अन्य पिछड़े वर्गों के एक हिस्से ने भी आंदोलन की राह पकड़ी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने इन तीनों आंदोलनों के युवा नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया। उधर अनुमान लगाया गया कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदमों से व्यापारी तबका नाराज हुआ होगा, जो आम तौर पर भाजपा का समर्थक रहा है। इन सबके आधार पर चर्चा चली कि इस बार गुजरात भाजपा के हाथ से निकल सकता है।

लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी ने भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाली, सूरत बदलनी शुरू हो गई। मोदी ने 34 रैलियों को संबोधित किया। चुनावी माहौल में वे यह साहसी बयान देने से भी नहीं चूके कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे देश हित में उठाए गए कदमों की राजनीतिक कीमत चुकाने को वे तैयार हैं। ऐसी टिप्पणियों से यह संदेश गया कि मोदी सरकार भारत के दूरगामी भविष्य को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक सुधार के फैसले ले रही है।

लोगों ने इसकी अहमियत समझी। सोमवार को वोटिंग मशीनें खुलीं, तो ये बात जाहिर हुई। मतदाताओं ने फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया। कांग्रेस के लिए ये गहरी मायूसी की खबर है। उसके नए अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने को गुजरात में पूरी तरह झोंक दिया था। इस बात के लिए तो उनकी तारीफ हुई कि उन्होंने जोशीला प्रचार अभियान चलाया और गुजरात में कभी मृतप्राय समझी जाने वाली कांग्रेस को लड़ाई में ला खड़ा किया। लेकिन आखिरकार उनकी पार्टी को लगभग तीन फीसदी वोट और कुछ सीटों की बढ़ोतरी के साथ ही संतोष करना होगा। उसके सामने यह कठोर हकीकत है कि जनता उसे ऐसी पार्टी के रूप में स्वीकार नहीं कर रही है, जिसे सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी जाए। यह उसके लिए गहरे आत्म-निरीक्षण का विषय है। ये तथ्य भी उल्लेखनीय है कि भाजपा की सीटों में जरूर गिरावट आई, लेकिन उसके वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई। फिर भी भाजपा को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि उसकी सीटें क्यों कम हुईं? फिलहाल, भाजपा को मोदी मैजिक का सहारा है। इसलिए प्रतिकूल स्थितियों में भी वह विजय प्राप्त कर रही है। मगर आदर्श स्थिति वो होगी, जब ऐसे हालात पैदा ही ना हों। भाजपा को ऐसा शासन देने की योजना बनानी चाहिए, जिससे लोग उत्साह के साथ उसे अपनी पहली पसंद बनाते रहें।

— (नई दुनिया, 19 दिसंबर)

गुजरात के नतीजे

नाटकीय बदलाव की उम्मीद तो पहले ही बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों को इस बात का श्रेय दिया ही जाना चाहिए कि उसने भारतीय राजनीति को एक दिलचस्प पड़ाव तक पहुंचा दिया है। चुनाव नतीजों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की तुलना पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार से की जा रही है, जिसने लंबे समय तक अजेय रहने का रिकॉर्ड बनाया था। राज्य के स्तर पर देखें, तो यह तुलना काफी हद तक ठीक भी नजर आती है। लेकिन इसे अखिल भारतीय परिदृश्य में देखें, तो भाजपा की विजय यात्रा का फलक कहीं ज्यादा व्यापक है। वाम मोर्चा पश्चिम बंगाल की जीत को त्रिपुरा से आगे कहीं नहीं ले जा सका था, क्योंकि केरल में तो वामपंथी सरकार पश्चिम बंगाल से भी पहले बन गई थी। जबकि भाजपा ने गुजरात से शुरू करके अपने फलक को अखिल भारतीय स्तर पर लगातार फैलाया है।

— (हिन्दुस्तान, 19 दिसंबर)

सूक्त विचार...

प्रगति स्वतंत्रता में निहित है। बिना स्वशासन के न औद्योगिक विकास संभव है, न ही राष्ट्र के लिए शैक्षिक योजनाओं की कोई उपयोगिता है, देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना सामाजिक सुधारों से अधिक महत्वपूर्ण है।

— बाल गंगाधर तिलक

हम चाहे सत्ता में हो या न हो, सभी भारतीयों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए, चाहे वह किसी लिंग, जाति, धर्म या भाषा से सम्बद्ध क्यों न हो, हम साथ–साथ मिलकर, कन्धे से कन्धा मिलाकर अपनी मातृभूमि को सुदृढ़, समृद्ध और स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए काम कर सकते हैं।

— कुशाभाऊ ठाकरे

प्रस्तुति: पंकज आनंद

आज ही लीजिए

कमल संदेश

की सदस्यता

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

और

दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

गुजरात और हिमाचल की विजय के बाद भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते श्री अमित शाह

चुनावी विजय के बाद हिमाचल प्रदेश के सांसदों से मिलते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

चुनावी जीत के बाद गुजरात के सांसदों से मिलते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

ओखी तूफान से प्रभावित लोगों से मिलते तथा लक्षद्वीप, तमिलनाडु और केरल में राहत कार्यों का जायजा लेते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद मेघालय स्थित शिलांग में एक विशाल रैली को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20